

अवैध मोरम खनन: मंजीत कॉटन की निर्माणाधीन जिनिंग का खेल

लालच देकर आपस में लड़वाकर आपसी भाईचारे को तार-तार करने का प्रयास



लालच देकर अवैध मोरम का खनन करवा रहा मंजीत कॉटन।

माही की गूंज, खवासा/झाबुआ।

मंजीत कॉटन फर्म एक बड़ा नाम है और कहते हैं जितना बड़ा नाम उतना बड़ा खराब काम। और मंजीत कॉटन के कर्मचारी उक्त पंक्ति को चरितार्थ करते हुए क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। जिले के साथ आस-पास जिले के कपास का व्यवसाय करने वाले मंजीत कॉटन बदनावर को भली भांति जानते हैं। जो क्षेत्र में उपज कपास का एक बड़ा हिस्सा बदनावर की मंजीत कॉटन द्वारा ही खरीदा जाता है और उक्त मंजीत कॉटन का रूई का बड़ा व्यापार दक्षिण भारत तक है।

उक्त मंजीत कॉटन की कपास की जिनिंग फैक्ट्री के बारे में बताते हैं बदनावर के साथ संधवा तथा महाराष्ट्र के साथ अन्य कई जगहों पर संचालित है। इसी कड़ी में झाबुआ जिले के खवासा क्षेत्र के ग्राम नरसिंगपाड़ा में भी मंजीत कॉटन जिनिंग फैक्ट्री का निर्माण एक बड़े रकबे में किया जा रहा है। कहने को यह जिनिंग फैक्ट्री क्षेत्र एवं जिले वासियों के लिए हर्ष की बात है। परंतु बाईनामी, 4 सौ बीसी व अवैध तरीके से निर्माण किया जाना तथा शिकायत के बाद अपने षड्यंत्रकारी पेटेरे को अपनाकर स्थानी भाईचारे को तार-तार करने का प्रयास कर अपना कार्य निकाले जाने इसे किसी भी स्थिति में सही नहीं कहा जा सकता है।

मामला यह कि, 55 से 60 बीघा में बन रही इस मंजीत कॉटन फैक्ट्री में मोरम लाखों घन मीटर की आवश्यकता लेवल हेतु है। जिसमें निर्माण कार्य शुरू होने के साथ बाहरी पोकलेन एवं बैकहोलोडर मशीनें लाकर ढोलखरा तालाब के साथ अन्य तालाब एवं शासकीय जगहो से दिन-रात करीब एक सप्ताह से अधिक दिनों तक डंपरों एवं ट्रैक्टरों से बड़ी मात्रा में अवैध मोरम का खनन कर उक्त जिनिंग फैक्ट्री में लाया गया। दिन रात मोरम खनन के चलते आमजनों को धूल



खनन कर उक्त निर्माणाधीन फैक्ट्री में मोरम लाया जा रहा है। ऐसे में हो यह रहा

कि, स्थानीय उपसरपंच के साथ अन्य शिकायतकर्ता राजस्व से लेकर खनिज विभाग तक के नीचे से ऊपर तक के अधिकारियों को अवैध मोरम खनन की शिकायत करते हैं। लेकिन सभी अधिकारी कोई न कोई बहाना बनाकर उक्त खनन होते समय कार्रवाई हेतु कोई नहीं आ रहे हैं। लेकिन यह जरूर जरूर हो रहा है कि, यह अधिकारी शिकायत की पूरी जानकारी कहीं न कहीं उक्त फैक्ट्री के निर्माणकर्ता संचालकों को दे रहे हैं। जिसके चलते स्थानीय शिकायतकर्ता एवं लालच में आकर अवैध मोरम ढोने वाले के मध्य आपसी में विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है।

वही फैक्ट्री के संचालक कर्ताओं ने स्पष्ट कह दिया कि, मोरम ढोते समय मशीन या ट्रैक्टर पकड़ते हैं तो उनकी कोई जवाबदारी नहीं है। ऐसे में फैक्ट्री में लालच के चलते टुकड़ों- टुकड़ों में मोरम भी आ रहा है और गांव में यह मोरम आपसी विवाद का कारण भी बन चुका है।

नवरात्रि के पूर्व सामने आया कि, स्थानीय मशीन से मोरम खनन कर कुछ ट्रैक्टर मोरम फैक्ट्री में ढो रहे थे कि, स्थानीय उपसरपंच ने हमारे प्रतिनिधि को जानकारी दी तथा साथ में मयथुफ के लिए रात्रि में बिठाकर भी उपसरपंच ले गया। तथा फोटो व वीडियो मोरम ढोते समय ट्रैक्टर ट्राली के लिये गए। जब यह जानकारी राजस्व से लेकर खनिज विभाग के अधिकारियों को उपसरपंच द्वारा मय फोटो वीडियो के साथ फिर शिकायत की गई। लेकिन कोई अधिकारी कार्रवाई हेतु नहीं आया। इसके बाद हुआ यह कि, यह जानकारी पुनः फैक्ट्री निर्माण संचालकों को लगी। तो एक और नया षड्यंत्र उप सरपंच के साथ पत्रकार के विरुद्ध भी रचने का प्रयास किया। और फैक्ट्री के एक निर्माणकर्ता संचालक

मिथ्री एवं आवाजाही में परेशानी होने पर शिकायतों का दौर चला और खनिज विभाग ने एक बार आकर एक बैकहोलोडर व ट्रैक्टर जप्त कर बैकहोलोडर पर करीब 1 लाख 15 हजार का जुर्माना लगाकर फैक्ट्री मालिक को क्लीन चिट दे दी।

जबकि जो मोरम अवैध रूप से खनन कर फैक्ट्री में लाया गया था वह हजारों नहीं बल्कि लाखों घनमीटर मोरम ला चुके थे। अगर खनिज विभाग फैक्ट्री के अंदर आए मोरम का आकलन निकालता तो तय है एक अनुमानित जुर्माना करोड़ों में पहुंचता।

लालच के दाने डाल अब आपस में लड़वाने का प्रयास

लेकिन खनिज विभाग ने शिकायतों पर महज अपनी खानापूर्ति कर ली। वहीं उक्त घटना के बाद मंजीत कॉटन फैक्ट्री के निर्माणकर्ता संचालक ने राजस्व से लेकर खनिज विभाग तक ऐसी सेंटिंग बिठाई की अब जो मोरम की आवश्यकता उक्त फैक्ट्री में है वह लाते समय शिकायत होने पर कोई अधिकारी मौके पर नहीं आ कर टालम टोल करेंगे।

वही षड्यंत्र के साथ फैक्ट्री के निर्माण संचालकों ने षड्यंत्र ऐसा रचा कि, बाहरी मशीनों को रवाना कर दिया और स्थानीय स्तर की मशीनों एवं ट्रैक्टरों संचालकों से अलग-अलग संपर्क कर प्रति ट्राली मोरम पर 7 सौ से 1 हजार रूपए तक अलग-अलग व्यक्ति को लालच रूपी ऑफर दे दिया गया जिसमें फैक्ट्री मालिक की कोई जवाबदेही नहीं कहा गया।

उक्त लालच में आकर कुछ स्थानीय बैकहोलोडर मशीन एवं ट्रैक्टर मालिक मौका देख अवैध मोरम का

कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल से 10 लाख रुपये की ठगी

माही की गूंज, उज्जैन। शहर में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है। इस बार ठगों ने आईटीआई कॉलेज के 80 वर्षीय सेवानिवृत्त प्राचार्य को निशाना बनाकर उनके बैंक खाते से 10 लाख रुपये निकाल लिए।माधव नगर पुलिस ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

पुलिस के अनुसार सनत कुमार जैन उम्र 80 वर्ष निवासी निर्माण नगर, सेठी नगर के पास, आईटीआई कॉलेज के सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं। रविवार को उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति का फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को एक बैंक का अधिकारी बताते हुए जैन को सिटीजन एटीएम कार्ड बनवाने का प्रस्ताव दिया और इससे कई सुविधाएं मिलने की बात कही।

फोन करने वाले ने बैंक खाते से संबंधित जानकारी ले ली

सनत कुमार जैन फोन करने वाले की बातों में आ गए और सिटीजन एटीएम कार्ड बनवाने के लिए सहमति दे दी। इसके बाद फोन करने वाले ने उनसे उनके बैंक खाते से संबंधित जानकारी, एटीएम का पिन और सीवीसी नंबर ले लिया। कुछ देर बाद सनत कुमार जैन ने इस संबंध में अपने पड़ोसी संजय को बताया। इस पर संजय ने जैन से कहा कि उनके साथ धोखाधड़ी हो गई है, उन्हें तुरंत इस संबंध में शिकायत करना चाहिए। बैंक से जानकारी लेने पर पता चला कि 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई है।

नवरात्र में गरबा का उत्साह चरम पर



रोय्या देवी मंदिर।

माही की गूंज, खवासा। शारदीय नवरात्र में गरबो का उत्साह चरम पर है।ग्राम के प्राचीनतम रोय्यादेवी मंदिर पर नवयुवक नवदुर्गा उत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित गरबा उत्सव में बड़ी संख्या में मातृशक्ति उत्साह और उमंग के साथ गरबा खेलने पहुंच रही है। यहां विगत 50 से अधिक वर्षों से गरबा खेला जा रहा है। वहीं बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर प्रांगण में संकट मोचन मित्र मंडल द्वारा केसरिया गरबा आयोजित किया जा रहा है। जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं गरबा खेलने पहुंच रही हैं। आकर्षक विद्युत साज-सज्जा और आधुनिक वाद्य यंत्रों पर गरबों की सुरीली आवाज में दोनों ही स्थानों पर देर रात तक गरबा खेल शक्ति स्वरूप माताजी की आराधना की जा रही है। वहीं प्राचीनतम शिव मंदिर पर अखंड जाप आयोजित किए जा रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में भी पावागढ़ से लाई जोत जलाकर गरबा खेला जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में गरबा खेला जा रहा है।



संकट मोचन प्रांगण।

गेहूं चने की फसल पर संकट, दो पानी देकर कहीं सूखा घोषित करने से बचने का तरीका तो नहीं

माही की गूंज,बरेटेट। जगदीश प्रजापत

अल्प वर्षा किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। किसान रबी फसल बोई तो भी नुकसान न बोई तो भी नुकसान। क्योंकि जलसंसाधन विभाग खरीब फसलों की सिंचाई के लिए दो पानी देने की बात कर रहा है। लेकिन दो पानी में ऐसी कोन सी फसल है, जो झाबुआ जिले की पथरीली जमीन पर पक जाए। किसानों की यह चिंता पूरी तरह से जायज है कि केवल दो पानी (दो बार सिंचाई) मिलने से फसल पूरी तरह नहीं पकती। रबी की फसलों, विशेषकर गेहूं को अच्छी उपज के लिए आमतौर पर 4 से 6 बार

सिंचाई (पानी) की आवश्यकता होती है। ऐसे में सिर्फ दो पानी मिलना किसानों के लिए भारी नुकसान का कारण बन सकता है।

किसानों और सरकार के बीच इस मुद्दे को लेकर मुख्य टकराव

फसल चक्र के अनुसार पानी की जरूरत है,दो पानी मिलने से फसल का शुरुआती विकास तो हो जाता है। लेकिन दाना बनते समय पानी न मिलने से फसल सूख जाती है या पैदावार बहुत कम यानी ना के बराबर हो जाती है।



- फाइन फोटो: सूखा घोषित आखिर कब।

किसानों का आरोप है कि, सरकार दो बार

पानी देकर यह दिखाना चाहती है कि से उसने सिंचाई के लिए मदद की है। ऐसा करने से तकनीकी रूप से उस क्षेत्र को संपूर्ण सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग कमजोर पड़ जाती है। जिससे किसानों को मिलने वाला मुआवजा या बीमा क्लेम का मामला उलझ सकता है।

एक पानी के बाद दूसरे पानी की कोई गारंटी नहीं

सिंचाई की शुरुआत में नहरों से पहला पानी छोड़ा जाएगा ये तय है लेकिन जिस तरह की परिस्थितिया वर्तमान में बनी हुई किसानों के

सामने खेती की शुरुवात के बाद दूसरे पानी के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। किसान संगठनों से समस्त प्रयास नर्मदा के पानी को माही डेम में लाने के असफल हो चुके हैं। पानी की कमी साफ देखी जा सकती है और सिंचाई के लिए एक बार का पानी छोड़ने के बाद डेम में पानी और कम होना ही है। कम वर्षा के चलते डेम से संचालित कई छोटे-बड़े शहरों की जल व्यवस्था प्रभावित होगी ऐसे में स्थिति अगर गंभीर होने की स्थिति में दूसरी बार पानी विभाग छोड़ेगा कि नहीं इसका निर्णय भी समय की मांग अनुसार होगा। ऐसे में किसानों के सामने फसल बोने से पहले दोहरी चुनौती होगी। डेम से मिलने वाले पानी के अलावा किसान मावठे की बारिश के लिए भी इंतजार करेंगे।

चौकी व्यवस्था अपडेट लेकिन स्टॉफ की कमी

माही की गूंज, खवासा।

यहां खवासा को पुलिस थाना मिलने की मांग हो रही है। वहीं खवासा चौकी स्टाफ की कमी के चलते पदस्थ पुलिस को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में पिछले दो-तीन माह पूर्व खवासा चौकी पर पदस्थ हुए चौकी प्रभारी एसआई अनिल गुरेया ने खवासा चौकी को कुछ अपडेट करने का प्रयास किया।

खवासा चौकी पर बीच में स्टाफ सम्मानजनक स्थिति में था लेकिन वर्तमान में और स्टाफ की कमी कर दी गई। जिससे पदस्थ पुलिस कर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खवासा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत करीब 50 गांव आते हैं ऐसे में यहां कम से कम जब तक थाना नहीं बने तब तक चौकी पर 15 से 20 पुलिस कर्मियों की पद स्थापना हो तो यहां की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में आधे से भी कम पुलिस कर्मचारी यहां पदस्थ है।

चौकी पर पुलिस वायरलेस सिग्नल की कमी भी रहती थी। वही जहां चौकी पर

स्टाफ की कमी है ऐसे में कोई भी पुलिसकर्मी खाना व नाश्ता करने पर भी जाए तो उसे चौकी छोड़ जाना होता था ऐसे में कई बार चौकी प



चौकी प्रभारी के प्रयास से लगा टावर व चौकी कक्ष में ही किचन की व्यवस्था।

व्यवस्था को सुधार करते हुए नवीन चौकी प्रभारी अनिल गुरेया ने चौकी को अपडेट करते हुए सर्वप्रथम एसपी कार्यालय से पुलिस वायरलेस सेट के सिग्नल के समाधान हेतु चौकी परिसर में टावर लगाने की मांग की। तत्पश्चात खवासा चौकी में टावर लग वायरलेस सिग्नल की समस्या का समाधान हो गया है। अब खवासा चौकी का वायरलेस सेट का सिग्नल ईतना प्रभावी हो

गया कि, जिले की चौकी-थाना के सिग्नलों से संपर्क के साथ आसपास एमपी के जिलों के पुलिस थाने-चौकी के भी सिग्नल भी यहां मिल रहे हैं। वहीं पुलिस चौकी में ही पीछे एक कक्ष में किचन शेड बनाकर एक खाना बनाने वाला व्यक्ति की व्यवस्था कर दी गई। जिससे यह फायदा की कोई भी पुलिस

कर्मचारी खाने व नाश्ते के नाम पर रूम या चौकी के बाहर नहीं जाना पड़ता है। जिससे चौकी पर कोई न कोई पुलिस जवान मिल सकता है।

वही चौकी प्रभारी ने चौकी बाउंड्री पर मेड लगाकर धूल मिट्टी का बचाव करने का प्रयास किया। चौकी प्रभारी द्वारा किए गए ये प्रयास वास्तविक रूप से सराहनीय है।

संकुल का दर्जा मिलने के बाद भी अतिथियों के भरोसे शासकीय हाई स्कूल



माही की गूंज, भामल/खवासा।

खवासा शासकीय बालक हाई सेकेंडरी स्कूल को सीएम राइस स्कूल बनाने के साथ इस स्कूल का संकुल क्षेत्र समाप्त कर भामल की शासकीय हाई स्कूल को संकुल का दर्जा दिया गया। लेकिन भामल की शासकीय हाई स्कूल को भले ही संकुल का दर्जा प्राप्त हो गया। लेकिन जो संकुल स्तरीय स्कूल को सुविधाएं प्राप्त होना चाहिए उन सुविधाओं के अभाव में आज भी यह हाई स्कूल अपने आंसू बहा रही है।

सर्वप्रथम संकुल का दर्जा मिलने के साथ उक्त शासकीय हाई स्कूल में विषय वार समस्त स्थाई शिक्षकों की पद स्थापना की जाना अनिवार्य थी। लेकिन उक्त संकुल में 156 विद्यार्थी अध्ययनरत होकर 6 कमरों वाली स्कूल में एक कक्ष पुस्तकालय का तो एक कक्ष प्रयोगशाला के रूप में उपयोग होकर 4 कक्षों में विद्यालय का संचालन हो रहा है। वही सिर्फ एक स्थाई शिक्षक जोकि संस्था के प्रभावी प्राचार्य सकन सिंह निनामा है। इसके अलावा 6 अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई। ऐसे में स्थाई शिक्षक उर्फ प्रभावी प्राचार्य की मजबूरी यह रहती है कि, उन्हें शासकीय स्कूल संबंधित अन्य कार्यों में अपनी व्यवस्थता रहती है इस स्थिति में संकुल दर्जा प्राप्त यह हाई स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे ही संचालित हो रही है। ऐसे में उक्त संकुल का दर्जा प्राप्त स्कूल में अन्य सुविधाओं की अपेक्षा करना क्षेत्र वासियों के लिए बेमानी ही साबित हो रहा है।

राजनीतिक जनप्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र वासियों की मांग है कि, भामल उक्त बालक हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी का दर्जा दिया जाए। साथ ही उक्त संकुल में विषय वार समस्त स्थाई शिक्षकों की पद स्थापना के साथ संकुल स्कूल को जो सुविधा भवन एवं शिक्षा संबंधित होती है वह सभी सुविधा पूर्ण की जाए।

'लोड शेडिंग: जूनियर इंजीनियर उपस्थित रहकर त्वरित करें समाधान

माही की गूंज, झाबुआ। विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में विद्युत की मांग, आपूर्ति एवं लोड शेडिंग की स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने विद्युत कटौती के दौरान आमजन को होने वाली असुविधाओं को न्यूनतम रखने तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में विद्युत विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि, जिले में वर्ष 2025 में प्रतिदिन विद्युत की मांग लगभग 100 मेगावाट थी, जो वर्तमान वर्ष में बढ़कर 150 मेगावाट हो गई है। इसी प्रकार राज्य में इस वर्ष प्रतिदिन विद्युत की मांग लगभग 15 हजार मेगावाट है। विद्युत उत्पादन एवं मांग में अंतर होने के कारण लोड शेडिंग के माध्यम से विद्युत आपूर्ति का प्रबंधन किया जा रहा है। कलेक्टर डॉ. भरसट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि, लोड शेडिंग के लिए निर्धारित समय-सीमा से अधिक विद्युत कटौती किसी भी स्थिति में नहीं की जाए। उन्होंने कहा कि, निर्धारित अवधि से अधिक विद्युत कटौती होने पर उपभोक्ता विद्युत विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने सभी इंजीनियरों को निर्देशित किया कि उपभोक्ताओं के फोन कॉल अनिवार्य रूप से रिसीव करें।

सरपंचों के तीन कार्यकाल के बाद भी पंचायत भवन अधूरा

नारेला पंचायत में सरकारी राशि के उपयोग पर उठे सवाल, ग्रामीणों ने की जांच और रिकवरी की मांग

माही की गूंज, मामल/खवासा। सुनील सोलंकी

ग्राम पंचायत नारेला में वर्ष 2013-14 के दौरान निर्मित पंचायत भवन आज तक अधूरा पड़ा होने का मामला सामने आया है। वर्षों बीत जाने के बावजूद भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने से जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गांव के लोगो का कहना है कि, पंचायत भवन को पूर्ण कराने के लिए आज दिनांक तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते भवन अपनी दुर्दशा पर आंसु बहा रहा है।

ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, 2013-14 मे यह भवन स्वीकृत हुआ था और उस समय बालू वसुनिया सरपंच थे। तथा फिर चुनाव आए तो कुंवरी पति शम्भु डोडीयार सरपंच बनी उसके बाद फिर बालू वसुनिया सरपंच बने जो अभी वर्तमान मे भी है, फिर भी भवन का कोई सुधार ही नहीं हुआ। ग्रामीणों के अनुसार पूर्व सरपंच कुंवरी बाई पर रिकवरी के आदेश भी जारी हुए है। लेकिन फिर भी पंचायत भवन बना ही नहीं। उम्मीद थी कि भवन तैयार होने के बाद ग्राम पंचायत के कामकाज को व्यवस्थित तरीके

से संचालित किया जाएगा। और ग्रामीणों को पंचायत से संबंधित कार्यों के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। लेकिन वर्षों गुजर जाने के बाद भी भवन अधूरा पड़ा है। इससे शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन और निर्माण कार्यों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि, पंचायत भवन की दुर्दशा किसी एक दिन में नहीं हुई, बल्कि लंबे समय से इसकी अनदेखी की जाती रही है। दो सरपंचों के तिन कार्यकाल बीत जाने के बावजूद भवन को पूर्ण कराने की दिशा में अपेक्षित पहल नहीं हुई। आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि वर्ष 2013-14 में शुरू हुआ निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हो सका ? निर्माण के लिए स्वीकृत राशि का कितना उपयोग हुआ और भवन अधूरा क्यों छोड़ दिया गया? इन सवालों का जवाब ग्रामीण, जिम्मेदारों से चाहते हैं।

सरकारी राशि के उपयोग की हो निष्पक्ष जांच

ग्रामीणों की मांग है कि, पंचायत भवन निर्माण से जुड़े सभी दस्तावेजों, स्वीकृत राशि, जारी भुगतान, निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति और संबंधित अभिलेखों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। जांच में यह स्पष्ट किया जाए कि, भवन निर्माण के लिए

कितनी राशि स्वीकृत हुई, कितनी राशि खर्च दर्शाई गई और वास्तविकता में कितना कार्य हुआ।

ग्रामीणों का कहना है कि, यदि जांच में सरकारी राशि के दुरुपयोग या अनियमितता की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए तथा नियमानुसार राशि की वसूली भी की जाए। साथ ही अधूरे भवन को पूर्ण कराने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएं ताकि सरकारी संपत्ति का उपयोग हो सके।

जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करना जरूरी

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए राशि उपलब्ध कराती है, ताकि लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। लेकिन जब वर्षों पहले शुरू हुआ पंचायत भवन आज भी अधूरा पड़ा रहे। तो निर्माण कार्यों की निगरानी और जवाबदेही पर



पटवारी कक्ष होने के बावजूद नहीं बैठते पटवारी साहब, ग्रामीण परेशान

माही की गूंज, सागवा/खवासा। प्रवेश चौहान

ग्राम पंचायत सागवा में पटवारी के बैठने के लिए कक्ष का निर्माण होने के बावजूद पटवारी के यहां नहीं बैठने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, पटवारी साहब खवासा उप तहसील में बैठते हैं, जिसके कारण सागवा और पाटड़ी के आसपास के ग्रामीणों को अपने राजस्व संबंधी कार्यों के लिए खवासा जाना पड़ता है। इससे ग्रामीणों का समय और पैसा दोनों खर्च हो रहे हैं। ग्रामीण हुका भाभर, दला निनामा, सबूड़ी मैड़ा आदि का कहना है कि, जब शासन द्वारा सागवा में पटवारी के बैठने के लिए भवन का निर्माण करवाया गया है तो इसका उपयोग भी होना चाहिए। वर्तमान में भवन की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि, लंबे समय से यहां नियमित शा.गतिविधियां नहीं हो रही हैं। भवन के आसपास घास-फूस उग आई है और परिसर की साफ-सफाई पर भी किसी का ध्यान नहीं है।

खवासा जाने में उठाना पड़ता है अतिरिक्त खर्च

ग्रामीणों को पटवारी से संबंधित कार्यों, दस्तावेजों और राजस्व मामलों के लिए खवासा उप तहसील जाना पड़ता है। इससे आने-जाने में अतिरिक्त किराया और समय खर्च होता है। खासकर किसानों और दूरदराज से आने वाले ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि, पटवारी कभी कभार आते भी है तो पंचायत पर बैठते हैं, पटवारी भवन पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जबकि यह भवन काफी समय से अनुउपयोगी पड़ा हुआ है। यहां पदस्थ लालचंद बबेरीय पटवारी की हटधर्मिता के कारण ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, यदि पटवारी गांव में निर्धारित दिनों पर उपलब्ध रहें, तो उन्हें छोटी-छोटी समस्याओं के लिए दूरसे स्थान पर नहीं जाना पड़ेगा।

सप्ताह में दो दिन बैठने की मांग

लोगो ने मांग की है कि, पटवारी साहब सागवा स्थित अपने कक्ष में कम से कम सप्ताह में दो दिन नियमित रूप से बैठें। ताकि ग्रामीणों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए भटकना न पड़े। साथ ही, भवन की साफ-सफाई और रख रखाव भी करवाया जाए, जिससे सरकारी भवन का उद्देश्य पूरा हो सके।



सनसनीखेज लुट की वारदात से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल

बेखौफ लुटेरों ने लैब टेक्नीशियन के परिवार को बनाया निशाना, एसपी ने किया घटनास्थल का मुआयना

माही की गूंज, पेटलावद।

एक के बाद एक हत्या के मामले सुलझाने वाली पेटलावद पुलिस चोरी और लुट-डकैती की वारदातों को ट्रेस करने में अपना पराक्रम नहीं दिखा पा रही है। जिसके चलते अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। क्षेत्र में लुटेरों ने फिर एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए लुट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। पुलिस को चुनौती देकर लुट की वारदात करने वालों तक पुलिस वारदात के चार से पांच दिन बीत जाने के बाद भी अपराधियों का सुराग नहीं लगा सकी है। वारदात पेटलावद थाना क्षेत्र के ग्राम उर्वाई में कल्याणपुरा के सरकारी अस्पताल में पदस्थ लैब टेक्नीशियन जयंत रावत के घर में नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोल लुट की वारदातों को अंजाम दिया। हथियारों के बल पर पूरे परिवार को बंधक बनाकर बदमाशों ने करीब दो लाख रुपए नकद और सोने-चांदी के कीमती जेवरात लुट लिए। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी देवेन्द्र पाटीदार ने शनिवार की देर शाम घटनास्थल का मुआयना किया और आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमों को कड़े निर्देश दिए हैं।

फरियादी जयंत रावत उर्वाई ने पुलिस को बताया कि, वे अपनी पत्नी रजनी, मां निमला और 9 वर्षीय बेटे रिधवन के साथ घर में सो रहे थे। रात करीब 1 बजे 6-7 अज्ञात बदमाशों ने दरवाजे पर लोहे की सबल से वार कर उसे तोड़ दिया और जबरन अंदर घुस गए। विरोध करने पर बदमाशों ने लोहे की सबल से जयंत की पत्नी के हाथ की कलाई पर चोट पहुंचाई और जयंत की कमर पर जान लेवा कुल्हाड़ी से वार किया। इसके बाद कुल्हाड़ी और कट्टे का डर दिखाकर पूरे परिवार को चुपचाप पलंग पर बैठने की धमकी दी। बदमाशों ने घर की अलमारियों को खंगालकर सोने की चेन, टाप्स, अंगूठी और चांदी के कंदोरा, साकली, पायजेब समेत करीब दो लाख रुपए नकद और एक वनस्पस मोबाइल लुट लिया और पीछे के रास्ते से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 मौके पर पहुंची और आसपास के ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। पीड़ित ने कोदली और उर्वाई के आसपास बदमाशों की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद धायल पत्नी का पेटलावद अस्पताल में



मध्याह्न भोजन का भुगतान अटका, दीपावली से पहले राशि जारी करने की मांग

माही की गूंज, खंडवा।

पुनासा विकासखंड के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले महिला स्व-सहायता समूहों को पिछले पांच महीने से भुगतान नहीं मिला है। भोजन बनाने वाले रसोइयों की मजदूरी भी बकाया है। भुगतान नहीं होने से समूहों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष उत्तमपाल सिंह पुरनी ने कलेक्टर को पत्र लिखकर दीपावली से पहले लंबित राशि जारी करने की मांग की।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने पत्र में बताया कि प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत जून से अक्टूबर 2026 तक भोजन सामग्री की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाले रसोइयों की मजदूरी भी लंबित है। राशि नहीं मिलने से महिला स्व-सहायता समूहों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। हालांकि, कुल बकाया राशि और प्रभावित समूहों की संख्या की जानकारी सामने नहीं आई है।

महिला स्व-सहायता समूह सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने के लिए किराना दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं से सामग्री खरीदते हैं। पांच महीने से भुगतान अटका होने के कारण समूहों को दुकानदारों का बकाया चुकाने में परेशानी हो रही है। इससे समूहों के कामकाज और उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पुरनी ने मांग की है कि दीपावली से पहले भोजन सामग्री की बकाया राशि जारी करने के साथ ही रसोइयों की मजदूरी का भुगतान भी कराया जाए। उन्होंने कलेक्टर से भविष्य में भुगतान नियमित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। पुरनी ने आशंका जताई कि भुगतान में लगातार देरी होने से स्कूलों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

बिजली कटौती पर कांग्रेस ने दिया दो दिन का अल्टीमेटम

माही की गूंज, खरगोना।

जिले में लगातार हो रही बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस ने सरकार को दो दिन का अल्टीमेटम दिया है। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक रवि जोशी ने चेतावनी दी कि यदि बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस आमजन के साथ मिलकर सांसद और विधायकों के आवास का घेराव करेगी।

रवि जोशी ने कहा कि नवरात्रि के दौरान शहरों से लेकर गांवों तक बिजली गुल रहने से श्रद्धालुओं, मजदूरों, किसानों और विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बिजली की सामान्य मांग 16 हजार मेगावाट है, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त कदम क्यों नहीं उठाए गए। उन्होंने कोयला खरीदी में गड़बड़ी होने का आरोप भी लगाया।

सरकार से दो दिन के भीतर बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग की।

जल संचय अभियान के अंतर्गत पंचायत स्तरीय जल चौपाल आयोजित

माही की गूंज, पेटलावद।

जिले में जल संकट की गंभीर स्थिति को देखते हुए कलेक्टर के निर्देशानुसार 16 अक्टूबर तक विशेष जल संचय अभियान चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के अंतर्गत 12 अक्टूबर को विकासखंड पेटलावद में सेक्टर सारंगी के अंतर्गत ग्राम पंचायत सारंगी, बरवेट, हमीरगढ़, देवली, गोपालपुरा (गामड़ी) में जल चौपाल बैठक का आयोजन किया गया। जल चौपाल में समस्त विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उपस्थित ग्रामीणों के साथ जल संरक्षण, जल संवर्धन, दैनिक जीवन में जल का महत्व, जल का सदुपयोग, वर्षा जल संचयन एवं कृषि कार्यप्रणाली पर संवाद किया गया।

जल संचयन अभियान के अंतर्गत 12 अक्टूबर को विकासखंड पेटलावद में सेक्टर सारंगी के अंतर्गत ग्राम पंचायत सारंगी, बरवेट, हमीरगढ़, देवली, गोपालपुरा (गामड़ी) में जल चौपाल बैठक का आयोजन किया गया। जल चौपाल में समस्त विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उपस्थित ग्रामीणों के साथ जल संरक्षण, जल संवर्धन, दैनिक जीवन में जल का महत्व, जल का सदुपयोग, वर्षा जल संचयन तथा भविष्य के लिए जल स्रोतों को सुरक्षित रखने के प्रति जागरूक किया गया। सामूहिक श्रमदान से साफ-सफाई, कुओं, बावड़ियों, हैंडपंपों, नदियों, नालों की साफ-सफाई एवं गहरीकरण, कम पानी वाली फसलों को लगाने हेतु प्रेरित करने और बोरी बंधान कार्य पर विशेष चर्चा की गई। साथ ही सभी ग्रामीणों को जल संरक्षण कार्यों में सक्रिय सहभागिता करने एवं पानी की प्रत्येक बूंद का महत्व समझते हुए जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में सरपंच, जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी जिसमें - जनपद पंचायत, ग्रामीण विकास विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत एवं पंचायत सचिवालय, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जन अभियान परिषद के मेंटर, नवांकुर संस्था, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के सदस्य, छात्र-छात्राएं एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।



मध्याह्न भोजन व्यवस्था पर फिर खड़े हुए सवाल, चार माह से मध्याह्न भोजन और रसोइयनों के भुगतान बकाया

माही की गूंज, पेटलावद।

झाबुआ जिले सहित पूरे मध्य प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत स्वयं सहायता समूहों एवं विद्यालयों में भोजन बनाने वाले रसोइया साधियों को पिछले चार माह से भुगतान नहीं मिलने से आर्थिक संकट की स्थिति निर्मित हो गई है। समूह संचालकों को भोजन संचालन की राशि नहीं मिलने से जहां खाद्य सामग्री की व्यवस्था करने में परेशानी आ रही है। वहीं रसोइया साधियों को भी मानदेय के अभाव में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर सोमवार को अखिल भारतीय स्वयं सहायता समूह एवं रसोइया संघ के नेतृत्व में पेटलावद क्षेत्र के विभिन्न समूहों के अध्यक्ष, सचिव एवं रसोइया साधियों ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेटलावद को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से शासन एवं संबंधित विभाग का ध्यान चार माह से लंबित भुगतान की समस्या की ओर आकर्षित किया गया।

ज्ञापन में बताया गया कि, मध्याह्न भोजन योजना के तहत विद्यालयों में भोजन संचालन करने वाले स्वयं सहायता समूहों को पिछले चार माह से राशि प्राप्त नहीं हुई है। वहीं, बच्चों के लिए नियमित रूप से भोजन तैयार करने वाले रसोइया साधियों को भी चार माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान में लगातार देरी होने से समूहों को खाद्य सामग्री खरीदने एवं भोजन व्यवस्था संचालित करने में परेशानी हो रही है। संघ ने मांग की कि, समूहों की लंबित राशि का तत्काल भुगतान किया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक राशि संबंधित समूहों के बैंक खातों में जमा करवाई जाए। इसके साथ ही रसोइया साधियों का बकाया मानदेय भी शीघ्र जारी करने की मांग उठाई गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान अखिल भारतीय वनवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहु सिंह भाभर, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री सोमजी भूरिया, भारत का मातृसंघ के जिला अध्यक्ष मोहन प्रजापत, जिला मंत्री मेहर सिंह सोलंकी, समूह संघ अध्यक्ष राधा डामर, सुरजी भगोरा सहित अन्य पदाधिकारी, समूह अध्यक्ष, सचिव एवं रसोइया साथी उपस्थित रहे। सभी ने शासन से मध्याह्न भोजन योजना से जुड़े समूहों एवं रसोइयों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण कर लंबित भुगतान जारी करने की मांग की।

26 अक्टूबर को होगा प्रदेशव्यापी आंदोलन

ज्ञापन सौंपने के साथ ही आयोजित बैठक में आपाभी 26 अक्टूबर को प्रदेशव्यापी एक दिवसीय आंदोलन करने की पररेखा भी तैयार की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि, भुगतान की समस्या का निराकरण हेतु 26 अक्टूबर को प्रदेशभर में आंदोलन किया जाएगा। इसमें पेटलावद तहसील से सैकड़ों की संख्या में स्वयं सहायता समूहों के अध्यक्ष, सचिव एवं रसोइया साथी शामिल होंगे। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि, समूहों एवं रसोइया साधियों की जायज मांगों को लेकर एकजुट होकर आवाज बुलंद की जाएगी

तथा शासन स्तर पर लंबित भुगतान के निराकरण के लिए दबाव बनाया जाएगा।

मध्याह्न भोजन व्यवस्था की मानिट्रिंग की कमी

एक और समूह को भुगतान नहीं हो रहा है तो दूसरी और कई समूह अपने जेब से व्यवस्था बनाए रखे हुए हैं। तो कई स्थानों पर राशि मिलने के अभाव में मध्याह्न

भोजन बच्चों तक समय से नहीं पहुंच रहा है। शासन द्वारा निर्धारित मेन्यू से तो कुछ स्कूलों में अपवाद स्वरूप मध्याह्न भोजन मिल रहा है। कई स्कूल और आंगनवाड़ी में बच्चों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। मध्याह्न भोजन व्यवस्था को लेकर विभाग पूरी तरह से लापरवाह है। किसी तरह की मानिट्रिंग मध्याह्न भोजन व्यवस्था की नहीं की जा रही है। आंगनवाड़ियों में तो स्थिति बद से बतर है।



संपादकीय

संवैधानिक आज़ादी की रक्षा हो- सुप्रीम कोर्ट

पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों पर सरकार की सख्ती के उपरांत सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप यह बताता है कि कानून-व्यवस्था बनाये रखने के नाम पर संविधान द्वारा नागरिकों को मिली आजादी का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। कोर्ट द्वारा हिरासत में रखे लोगों को रिहा करने, मेट्रो सेवाएं बहाल करने तथा इंटरनेट सुविधा यथाशीघ्र चालू करने का निर्देश देकर कोर्ट ने साफ संदेश देने का प्रयास किया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र में एक मूलभूत अधिकार है, न कि सरकार द्वारा दी गई सुविधा। उल्लेखनीय है कि गत दस अक्तूबर को कॉन्ग्रेस जनता पार्टी और कुछ अन्य संगठनों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। जिसको रोकने के लिये दिल्ली सरकार ने अभूतपूर्व सुरक्षा उपाय किए थे। इस दौरान सात हजार से अधिक लोगों को हिरासत में लिए जाने को लेकर सवाल उठाये गए। लोगों ने जगह-जगह सड़कों पर अवरोधक लगाने, क्षेत्र के मेट्रो स्टेशनों पर बंदिश लगाने तथा प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध सख्ती को लेकर चिंता जाहिर की। कहा गया कि पुलिस ने एहतियाती दायित्वों से बढ़कर आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। निरसंदेह, आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जवाबदेही अधिकारियों की बनती है। जब आंदोलन आदि के दौरान हिंसा होने और सार्वजनिक व्यवस्था भंग होने की आशंका हो तो आसन्न खतरों के मद्देनजर अधिकारियों की कार्रवाई करना बनता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि इन अधिकारों का उपयोग कानून की सीमाओं में ही किया जा सकता है।

लेकिन सवाल है कि सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने पर लोगों को हिरासत में लेना, निर्धारित निषेधाज्ञा वाले इलाकों से बहुत दूर तक आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना, सार्वजनिक सेवाओं पर रोक लगो तो क्या यह आम लोगों को दंड देने जैसा नहीं है? तभी शीर्ष अदालत ने कोर्ट-परिसर के आस-पास रोक लगाने वाले नोटिस भी तुरंत हटाने के निर्देश दिए। जिससे नागरिक-अधिवक्ता बिना किसी बाधा के यहां पहुंच सकें। दरअसल, विपक्षी दल लोगों को हिरासत में रखने और जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग की निष्पक्ष जांच की भी मांग कर रहे हैं। निरसंदेह, पुलिस को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। बेशक, प्रदर्शनकारियों के साथ ही कानून लागू करने वाली एजेंसियों को भी जवाबदेह बनाया जाए। यह एक हकीकत है कि देश के लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता का भरोसा विश्वसनीय जवाबों, खुली व निष्पक्ष जांच और संस्थागत आजादी पर ही निर्भर करता है। वहीं एक मजबूत लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को लेकर संशय नहीं होना चाहिए। जरूरी है कि वह असंतुष्ट लोगों की शिकायतों को सुनें, असहमति का सम्मान करते हुए कानून-व्यवस्था बनाये रखें और अदालत के निर्देशों का सम्मान करें। निरसंदेह, शीर्ष अदालत ने एक महत्वपूर्ण सीमा-रेखा खींची है। इसी आलोक में सरकार को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश की राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों में संविधान प्रदत्त स्वतंत्रता का अतिक्रमण न हो। हालांकि, सीजेपी व विपक्ष के तेषरों को देखते हुए यह करना आसान भी नहीं होगा।

चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ते बाजारीकरण का संकट



चंद्रकांत लहरीया

भारतीय निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पिछले चार दशकों में बने सामाजिक और नैतिक संकट का सामना कर रहा है। इसकी शुरुआत अस्पताल क्षेत्र में कॉर्पोरेट घरानों के प्रवेश से हुई और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वेंचर कैपिटल एवं निजी निवेश से इसने रफ्तार पकड़ी। यह संकट ढांचागत है। निजी स्वास्थ्य सेवा के विकास ने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं, जिनमें डॉक्टरों से अस्पतालों, दवा कंपनियों और संबंधित हितधारकों के लिए मुनाफा कमाने की अपेक्षा की जाती है। उपचार निर्णय, जोकि रोगी की जरूरत से निर्धारित होना चाहिए, उस पर व्यावसायिक प्रोत्साहनों और चिकित्साकरण का प्रभाव हावी हो गया है।

इस परिवर्तन ने डॉक्टर-रोगी संबंध को बदल डाला। चिकित्सक अब मात्र स्वतंत्र पेशेवर नहीं रह गया जो रोगी के प्रति जवाबदेह हो। कई डॉक्टर नैतिक बने हुए हैं और कई कॉर्पोरेट अस्पताल भी उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं, तथापि 'प्रोत्साहन रूपी लालच' पेशेवर आजादी कायम रखना मुश्किल कर देता है।

मसलन कॉर्पोरेट अस्पतालों में डॉक्टरों को वेतन तो मिलता है, लेकिन मालिकों की अपेक्षा होती है कि वे अधिकाधिक कमाई कर दिखाएं, रोगी संख्या बढ़ाएं, जांच, भर्ती और इलाज प्रक्रियाओं में अधिक मुनाफा बनवाएं। भारत में स्वास्थ्य सेवा के कॉर्पोरेटीकरण पर एक शोध में उपाजर्ज लक्ष्य, डॉक्टरों सलाह को अस्पताल भर्ती में परिवर्तित करने या एक-दो दिन वाले इलाज को लंबा खींचने को दबाव बनाने और घटती स्वायत्तता को र्ज किया है।

ऐसे रंग-ढंग ने 'अच्छे' डॉक्टर की परिभाषा बदल दी है। जो चिकित्सक मरीजों

को नेक डॉक्टरों सलाह देते हैं, बीमारी पर सावधानी भरा इंतजार करने की सलाह देते हैं या किसी महंगी प्रक्रिया से बचने की सलाह देते हैं, वे अधिक टेस्ट और उपचार करवाने वाले डॉक्टर की तुलना में कम पैसा कमाते हैं। एक बार जब व्यावसायिक उत्पादकता कार्य क्षमता का पैमाना बन जाए तो नेक इशारे वाले डॉक्टर भी मरीजों के हितों के विपरीत 'प्रोत्साहनों' के लालच में फंस सकते हैं। कई चिकित्सकों का इलाज के दाम तय करने,बिल बनाने या व्यावसायिक रणनीति पर दखल गण्य होता है, इसलिए विशेषज्ञता तो है लेकिन घटती स्वायत्तता के साथ।

दवा उत्पादन उद्योग में भी इसी किस्म की चिंताएं उपजी हैं। कंपनियां उत्तरोत्तर ऐसी रणनीतियों अपना रही हैं जिनसे बाजारीकरण और नेक चिकित्सा शिक्षा के बीच भेद करना मुश्किल हो रहा है। सम्मेलन,

सलाहकार बोर्ड, वक्ता कार्यक्रम और आतिथ्य सत्कार जैसे तरीकों ने इस लकीर को धुंधला कर रखा है। दवा उत्पादकों के लिए विक्री संबंधी सहिता में उपहार, यात्रा और आतिथ्य सत्कार जैसी सुविधाओं से डॉक्टरों को प्रभावित करने संबंधी निर्देश हैं, फिर भी यह गोरखधंधा सूक्ष्म तरीकों से काम करता है।

अस्पताल की निजी दवा विक्रेता दुकानें इस इकोसिस्टम का उदाहरण हैं। कई अस्पताल चुनिंदा ब्रांडों से भरी आंतरिक फार्मसियां संचालित करते हैं, डॉक्टरों को वहां रखी दवाएं ही लिखने को कहा जाता है। इससे मरीज का क्रय चयन सीमित हो जाता है और हॉस्पिटल की कमाई बढ़ जाती है।

पिछले 18 महीनों में मोटापा कम करने

वाली दवाओं की बढ़ती मांग इस तनाव को दिखाती है। जौएलपी-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट और उनसे जुड़ी दवाओं का फायदा सही में चुने गए मरीज को हो सकता है। फिर भी, सम्मेलनों और मेडिकल प्रचार शिविरों के जरिए की जाती इनकी आक्रामक मार्केटिंग पर सोचना जरूरी है। एक मेडिकल विशेषज्ञ ब्रांड एंबेसडर बनने की बजाय सुबूतों को समझने और व्याख्या करने वाला हो। उनकी भूमिका केवल यह बताना नहीं है कि दवा क्या कर सकती है, बल्कि यह बताना भी है



कि किसे इसकी जरूरत नहीं है, क्या अर्निक्षितताएं हैं, क्या-क्या बुरे असर और लागत है, कितने समय तक वास्तव में इलाज की जरूरत है, और दवा के बगैर कौन से उपचार ढंग का महत्व कायम है। कॉर्पोरेट स्वास्थ्य क्षेत्र में दवाएं तेजी से मुख्य भूमिका का आ रही हैं।

ये चिंताएं लंबे समय से चली आ रही हैं। 2018 में, समीरन नंदी, केशव देशिराजु और संजय नागराल ने 'स्वास्थ्य सेवा रक्षक या भक्षक? भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार' नामक पुस्तक संपादित की थी। इसमें हितों का टकराव, कॉर्पोरेट अस्पतालों के तौर-तरीके, दवा उत्पादक कंपनियों का प्रभाव, मेडिकल नियामन और व्यावसायिक नैतिकता की जांच की गई थी। आज भी

इसकी प्रासंगिकता चिंताजनक है। चिकित्सा जगत ने बार-बार इस समस्या की शिनाख्त तो की, लेकिन सुधार सीमित ही रहा।

कमजोर नियामन मुख्य समस्या है। भारत में डॉक्टरों के लिए नैतिकता सहिता और दवा उत्पादन की मार्केटिंग का नियंत्रण करने वाले नियम हैं। रेफरल कमीशन, गलत प्रोत्साहन और व्यापारिक प्रभावों के नाना तरीकों पर रोक है। फिर भी, क्रियान्वयन एक समान नहीं और अक्सर कार्रवाई शिकायतों या घोटालों के बाद होती है, न कि व्यवस्थित

निगरानी के जरिए। जब क्रियान्वन ही अर्निर्दिष्ट हो, तो नैतिक सहिता का कोई खास मतलब नहीं। फिर भी, भारत में हम दिखावे पर ज्यादा ध्यान देते हैं। 2022 में, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने मेडिकल पढ़ाई शुरू करने वाले छात्रों के लिए नई 'चरक शपथ' की सिफारिश की। मकसद इसे नए चिकित्सकों को ऐतिहासिक रूप से

दिलाई जाने वाली 'हिप्पोक्रेटिक शपथ' की जगह लेना था। हालांकि, दोनों सेवा व मरीज की भलाई को चिकित्सा पेशे के केंद्र में रखती हैं। पर शपथ वन दिखावा बनकर रह जाती है जब युवा डॉक्टर ऐसी जगह ट्रेनिंग लेते हों जहां व्यापारिक ध्येय, हितों का टकराव और गैर-जरूरी शपथ का सामाज्यीकरण हो चुका है। दखल से ज्यादा अहम है कि क्या संस्थान चिकित्सक को सिद्धांतों के अनुसार इलाज करने देते हैं। अन्य घटनाओं ने भी इन दबावों को बढ़ाया। देश में विशेषज्ञता वाली चिकित्सा शिक्षा तेजी से बढ़ने के मद्देनजर भारत खुद को मेडिकल टूरिज्म के मुकाम के तौर पर रख रहा है। दोनों के फायदे हैं, लेकिन इनसे अस्पताल नेटवर्क की आर्थिक ताकत ज्यादा

मजबूत हो सकती है। विशेषज्ञता वाले डॉक्टर आधारभूत ढांचा, रोग पहचान तंत्र, मरीज प्रवाह और अपनी व्यावसायिक पहचान के लिए संस्थानों पर निर्भर हो रहे हैं, जिससे क्लिनिक आधारित इलाज से कमाई की ताकत घट रही है।

मकसद पुराने दौर को बढ़िया बताकर पेश करना नहीं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सदा ही धन, पदानुक्रम और हितों का टकराव बना रहा है। न ही कॉर्पोरेट अस्पताल और न ही दवा उत्पादक कंपनियां अपने आप में अनैतिक होती हैं। चिंता यह है कि स्वास्थ्य सेवा का मतलब अब ज्यादातर दवाएं, टेस्ट, सप्लीमेंट्स, प्रोसीजर और ज्यादा खर्च बन गया है। डॉक्टर ऐसी चीजें सही ठहराने लगे हैं जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, और मरीजों को ऐसे इलाज भुगताने पड़ते हैं। अनिवार्य प्रश्न है कि क्या व्यापारिक लाभ चिकित्सकीय निर्णयों के अधीन बने रहें या उन पर हावी हो जाएं।

सभी तरह की शपथ का ध्येय है- चिकित्सा का वजुद सर्वप्रथम मरीज के हित में हो। पेशेवर आजादी, सही इलाज और जनता के भरोसे के लिए इस सिद्धांत को बनाए रखना जरूरी है। जब मरीजों को शक हो जाए कि परीक्षणों, दवा की पर्ची, इलाज प्रक्रिया में किसी और के पास भेजने या उपचार किया के पीछेछिपे आर्थिक मकसद हैं, तो इससे डॉक्टरों की नैतिक साख कमजोर होती है और स्वास्थ्य देखभाल मंडी सरीखा व्यापार बन जाता है।

भारतीय चिकित्सा के सामने संकट सिर्फ इलाज पर खर्च की मात्रा का नहीं, बल्कि इसका है कि चिकित्सा का स्वरूप क्या से क्या बनता जा रहा। भारत को एक ऐसे आधुनिक स्वास्थ्य तंत्र की जरूरत है जिसमें पूंजी इलाज करने में लगे, तकनीक उपचार में फँसले लेने में सहायक हो और संस्थान पेशेवर नैतिकता से समझौता करने के बजाय उसकी रक्षा करें। शपथ का महत्व तभी होता है जब व्यवस्था उसे निभाने का मौका दे।

पहाड़ रो नहीं सकते इसलिए दरकते हैं

सतलुज किनारे बसे उरनी गांव में एक स्थानीय निवासी अपने घर की दीवार पर पड़ी दगर को उगली से छूटा है, जैसे कोई बुजुर्ग अपने बच्चे का घाव सहलाता हो। गांव के नीचे से करछम वांगतू परियोजना की सुरंगें गुजरती हैं, और उस व्यक्ति की शिकायत मुआवजे से ज्यादा इस बात की है कि सुरंग बिछाने से पहले किसी ने उनसे पूछा तक नहीं। दशर देखने में छोटी है, पर उसमें एक पूरे समाज की अनसुनी पीड़ा दर्ज है।

यहीं विकास की हमारी परिभाषा कटघरे में खड़ी होती है। बिजली को प्रगति का पर्याय मान लिया और पहाड़ को ऐसा संसाधन, जिससे ऊर्जा निचोड़ी जा सके। जबकि पहाड़ किसी के लिए संसाधन है तो किसी के लिए घर, देवता और स्मृति। किन्नौर में सतलुज, बास्या और स्पीति की घाटियां दुनिया के सबसे नाजुक भूभागों में गिनी जाती हैं। वहीं तथापा-झाकड़ी जैसी डेढ़ हजार मेगावाट की परियोजना की मुख्य सुरंग लगभग सताईस किलोमीटर लंबी है। करछम वांगतू, बास्या-दो, कशांग और शोंगटोंग-करछम जैसी परियोजनाओं के साथ दर्जनों और प्रस्तावित हैं। हर परियोजना नदी को सुरंग में मोड़ती है और पहाड़ के भीतर किलोमीटरों लंबा खोलापन छेड़ जाती है। एक सुरंग का जोड़ पहाड़ शायद सह ले, पर जब एक ही घाटी में

सुरंगों की कतार लग जाए, तो उनका सामूहिक असर किसी एक परियोजना की रिपोर्ट में दर्ज नहीं होता। हमारे नियोजन की सबसे बड़ी वैचारिक चूक यही है कि हम पेड़ गिनते हैं और जंगल को नहीं देखते।

इस चूक की पहली कीमत पानी चुका रहा है, और पहाड़ में पानी का मतलब सिर्फ प्यास नहीं होता। वह बुजुर्गों की बनाई परंपरा है, खेत की सांस है, सब के बगीचों का भविष्य है और मवेशियों की जर्दगी है। पहाड़ के गांव नलकों से नहीं, प्राकृतिक स्रोतों से जीते हैं। सुरंग खोदते समय चट्टानों की जल-धाराएं कट जाती हैं और भूजल सुरंग में रिसकर बह जाता है। साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैमस, रिवर्स एंड पीपल ने करछम वांगतू के अरर में आए चौरांग, य्ला, उरनी, रुवांग, मीरू और चुवांग जैसे गांवों में स्रोतों के सूखने और जमीन की नमी घटने को दर्ज किया है।

भूस्खलन की तस्वीरें अखबारों में छपती हैं, पर सूखता हुआ झरना किसी सुखी में नहीं आता। जल पानी जाता है, वहां खेती जाती है, फिर रोजगार जाता है और अंत में लोग जाते हैं। इसी धीमी प्रक्रिया से आशंका है कि आने वाले दशकों में किन्नौर के गांवों से पलायन की



लहर उठे।

दीवारों की दरारें इसी कहानी का दूसरा अध्याय हैं। सुरंग के लिए होने वाली ब्लॉस्टिंग के कंपन घरों की नींव हिला देते हैं। निगुलसरी और झाकड़ी में मई, 2014 में दर्ज हुई दरारें, य्ला का फटा हुआ मकान और चुवांग की गौशाला की दीवारें, सब इसी सिलसिले की कड़ियां हैं। किन्नौर संविधान की पांचवीं अनुसूची का क्षेत्र है, जहां ग्राम सभा की भूमिका निर्णायक मानी गई है, फिर भी सुरंगों गांवों के नीचे से निकलती रहीं और लोगों को पता तब चला, जब उनके घर चटकने लगे।

वर्ष 2021 ने इस चेतावनी को और साफ कर दिया। जुलाई में बास्या घाटी के बटसेरी में पत्थर गिरने से नौ पर्यटकों की मौत हुई। अगस्त में राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर निगुलसरी में पहाड़ ऐसा दरका कि बस समेत कई वाहन मलबे में दब गए और क़रीब अठ्ठाईस लोग

नहीं लौटे। इसके बाद 'नो मीन्स नो' अभियान तेज हुआ और किन्नौर तथा लाहौल-स्पीति के कई गांव उससे जुड़े। स्थानीय लोगों का अनुभव यह है कि चट्टानों के गिरने और भूस्खलन की घटनाएं उन्हीं इलाकों में बढ़ी हैं, जहां बांध, पावरहाउस या सुरंगें बनी हैं।

हिमधारा कलेक्टिव के 2012 से 2016 के अध्ययन के अनुसार, 1980 से 2014 के बीच किन्नौर में गैर-वन कार्यों के लिए डायवर्ट हुई वन भूमि का लगभग नब्बे प्रतिशत हिस्सा जलविद्युत परियोजनाओं और ट्रांसमिशन लाइनों के हिस्से में गया। जंगल ढलानों को थामने वाली अदृश्य बांहे होते हैं। ऊपर से नदियों में फेंका गया मलबा बाढ़ की ताक़त को कई गुना कर देता है। किन्नौर ऊंचे भूकंपीय जोखिम वाला क्षेत्र है और 1975 का भूकंप आज भी याद दिलाता है। उधर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बादल फटने में और अचानक बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। वर्ष 2023 के मानसून ने पूरे हिमाचल में हजारों करोड़ रुपये का नुक़सान दिखाया। मौजूदा रफ़्तार नहीं बदली तो ऐसे संकट बार-बार लौटेंगे और हर बार पहले से भारी होंगे।

अब सवाल पूछने का वक़्त है। हरपरियोजना का आकलन अलग-अलग

क्यों होता है, जबकि पहाड़ एक ही है? किसी घाटी की धारण क्षमता और सभी परियोजनाओं के सामूहिक असर का अध्ययन कहाँ है? जिस मलबे का निपटारा नदी किनारे कर दिया गया, उसका हिसाब कौन देगा? जिन गांवों के स्रोत सूख गए, उन्हें स्थायी पेयजल देने की ज़म्मिंदारी किसकी है? इन सवालों के जवाब कोई एक दफ़्तर नहीं, पूरी व्यवस्था की नीयत देगी।

नई परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की पूर्व और सूचित सहमति को अनिवार्य शर्त बनाना होगा। पूरी सतलुज घाटी की धारण क्षमता और सामूहिक प्रभाव का अध्ययन होना चाहिए। जब तक वह पूरा न हो, नई स्वीकृतियां रुकनी चाहिए। मौजूदा सुरंगों के आसपास स्रोतों और दरारों का स्वतंत्र भूवैज्ञानिक ऑडिट हो और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। प्रभावित गांवों को वैकल्पिक पेयजल और उचित मुआवज़ा मिले, और मलबा निपटान के नियम काग़ज़ से उतरकर ज़मीन पर सख़्ती से लागू हों।



अमरेंद्र किशोर

यमन संघर्ष से फिर खाड़ी में युद्ध के बादल



भाषा सिंह

यमन में हूती विद्रोहियों और यमन सरकार के बीच चल रही लड़ाई विस्फोटक कगार पर पहुंच चुकी है। इसने ईरान युद्ध के बाद पश्चिम एशिया को फिर एक नए तनाव में धकेल दिया है। सऊदी अरब के दमम हवाई अड्डे पर भी 11 अक्तूबर को हमला हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। इससे पहले, शनिवार, 10 अक्तूबर को रियाद हवाई अड्डे पर हूतियों ने हमला बोला था, जिसमें एक भारतीय समेत 13 लोगों की मौत हुई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए।

इस हमले का दुनिया भर में कड़ा विरोध हुआ है। भारत ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब के मुख्य हवाई अड्डे पर हमला किया गया, जो निंदनीय है और किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे हमलों को तुरंत रोकना होगा। एक हफ्ते में रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और दमम हवाई अड्डे को मिलाकर सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर ये चौथा हमला है। दुनिया भर के देशों ने इन हमलों की निंदा की है।

हूती विद्रोहियों द्वारा लगातार सऊदी अरब को निशाना बनाकर हमले करने से खाड़ी के देशों और पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद इस बात की आशंका बलवती हो गई है कि क्या यमन में सत्ता की लड़ाई खाड़ी में

युद्ध की ज्वाला को भड़का सकती है, खासतौर से तब, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इसमें हस्तक्षेप करने की बात कही है। ट्रंप ने हूतियों के इन हमलों के खिलाफ सऊदी अरब के साथ उतरने की बात कही है, क्योंकि सऊदी अरब खाड़ी में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद दोस्त रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ईरान इस नए तनाव में अमेरिका का दखल नहीं चाहता और उसने हूतियों तथा सऊदी अरब के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है, ताकि इलाके का मसला इलाके में ही हल हो जाए।

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, हूती विद्रोहियों और यमन की सऊदी अरब समर्थित सरकार के बीच चल रहे सैन्य संघर्ष में अगस्त से अब तक 46 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हैस गुंडबर्ग ने चेतावनी दी है कि यमन में फिर से बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू हो सकता है, जो पूरे इलाके को अशांति में धकेल देगा। हैस ने जिस बात की ओर इशारा किया है, उसके मूल में यमन के भीतर और बाहर, यानी पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन के लिए चल रहा संघर्ष है। इसी दृष्टिकोण से सऊदी अरब के साथ मिलकर यमन की सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच चल रहे संघर्ष को समझा जाना चाहिए।

सऊदी अरब खाड़ी के सबसे बड़े, संपन्न और ताकतवर देशों में से एक है। वह खाड़ी के उन देशों में भी शामिल है, जिनके इस्तेमाल के साथ कूटनीतिक संबंध न होने के बावजूद उसके प्रति दोस्ताना व्यवहार रहा है। ईरान को सऊदी अरब भी पसंद नहीं करता। हूतियों के हमलों की ओमान,



ऑस्ट्रेलिया आदि कई देशों ने आलोचना की है।

इस संघर्ष का दूसरा पहलू यह है कि यमन की राजधानी सना, जहां 2014 से हूती विद्रोहियों का कब्जा है, वहां यमन सरकार लगातार हवाई हमले कर रही है। यमन की सरकार ने हूतियों के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की घोषणा की है, ताकि वह सना पर दोबारा कब्जा हासिल कर सके। राजधानी सना पर ये हमले 2023 में यमन की सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच हुए अंतरराष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन है। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को इसलिए निशाना बनाया है, क्योंकि वह यमन की सरकार का समर्थन कर रहा है। सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र से हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर हमले हो रहे हैं, जिन्हें हूती अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन बताते हैं। इस तरह यमन में चल रहे घरेलू सत्ता संघर्ष ने एक

अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का रूप ले लिया है।

यमन की स्थिति पेचीदा है। यहां यमन की सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच लंबे समय से गृहयुद्ध चल रहा है, जो पिछले कुछ समय से तेज हो गया है। यमन की राजधानी सना सहित उत्तर-पश्चिमी इलाके पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। हूती ईरान के करीबी माने जाते हैं, जबकि यमन की मान्यता प्राप्त सरकार के प्रमुख रशाद अल-अलीमी हैं और सरकार को सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त है। इस बीच, हूती विद्रोहियों और सरकार के बीच लड़ाई देश के भीतर इलाकों पर कब्जे तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें सऊदी अरब और लाल सागर के समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा तथा उन पर नियंत्रण का सवाल भी जुड़ गया है। चूंकि सऊदी अरब यमन सरकार को हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने के लिए सैन्य साजो-सामान मुहैया करा रहा है और उसकी मदद कर रहा है, इसलिए हूतियों ने सऊदी अरब को निशाना बनाया है।

इस हमले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। जिस तरह से तमाम देशों ने हूती हमले की निंदा की है, उससे सऊदी अरब की स्थिति मजबूत हुई है। सऊदी अरब पश्चिम एशिया में अमेरिका का दोस्त माना जाता है और ईरान के खिलाफ युद्ध में उसने अपने सैन्य अड्डे अमेरिका के इस्तेमाल के लिए मुहैया कराए थे। खाड़ी के देशों में सऊदी अरब का रुख शुरू से ही बिल्कुल अलग रहा है। यही वजह है कि ईरान पर अमेरिका और इस्राइल के हमले का मामला हो या फिर इस्राइल के फलस्तीन पर हमले का, इन सभी मामलों में

सऊदी अरब की भूमिका अहम रही है। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान भी एक पक्ष है, जिसने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता कर रखा है।

वैसे, हाल के दिनों में सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों की ओर से कई हमले किए गए हैं और इन हमलों में हवाई अड्डे मुख्य निशाना बने हैं। दरअसल, हूती विद्रोही इस बात से खासे नाराज हैं कि सऊदी अरब यमन सरकार की मदद कर रहा है, ताकि यमन की राजधानी सना पर सरकार का कब्जा हो सके। हूतियों का 2014 से यमन की राजधानी सना पर कब्जा है, जिसे वापस लेने के लिए यमन सरकार ने पूरी ताकत लगा रखी है। यमन सरकार को अपनी मदद जारी रखते हुए सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने 9 अक्तूबर को बताया था कि उसने तीन रॉकेट लॉन्च प्लेटफॉर्म नष्ट कर दिए हैं। गठबंधन के मुताबिक, हूती इनका इस्तेमाल क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए कर रहे थे। अब सऊदी अरब ने भी जवाब दिया है कि वह हूतियों के हमलों का जवाब देगा।

इस संघर्ष का एक अहम सिरा ईरान से भी जुड़ा हुआ है। हूती, जिन्हें अंसार अख़्बार यानी 'ईश्वर के समर्थक' कहा जाता है, ने ईरान के समर्थन में अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बाब अल-मदेब स्ट्रेट के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। यह जलअग्रमध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। यहां हूती विद्रोहियों की बढ़त ने अमेरिका और सऊदी अरब की रणनीति को झटका दिया था। हालांकि, हाल में यमन की सरकारी सेनाओं ने बाब अल-मदेब स्ट्रेट के पास बढ़त हासिल कर ली है। एक बार फिर खाड़ी देशों में संघर्ष और अशांति बढ़ी चिंता का विषय बनी हुई है।

मेरे भाई आईएएस और जीजा एसपी हैं

लाल किले में लेंगे जैन दीक्षा



माही की गूंज, मंदसौर/अरनोद।

आमतौर पर युवा पढ़ाई पूरी कर अच्छी नौकरी, बड़ा पद और सफल करियर बनाने का सपना देखते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद तो किसी के लिए भी करियर की नई ऊंचाइयां छूने के रास्ते खुल जाते हैं लेकिन अंकित जैन ने सांसारिक उपलब्धियों के बजाय संयम और आत्म कल्याण का मार्ग चुना। सातवीं कक्षा में अध्ययन करते समय ही मुनि बनने की भावना जग गई थी। कई बार प्रयास करने के बावजूद जब संकल्प पूरा नहीं हो सका तो पढ़ाई जारी रखी। प्रतापगढ़ से बीकानेर कर इंदौर में सीए की पढ़ाई पूरी की। आखिरकार सीए बनने के बाद सांसारिक जीवन छोड़कर जैन दीक्षा लेने का निर्णय किया। अब 25 अक्टूबर को दिल्ली के लाल किले में दीक्षा ग्रहण करेंगे।

7वीं कक्षा से ही मन में जाग्रत हुआ था वैराग्य का भाव

दीक्षा से पहले चल रहे कार्यक्रम के दौरान बातचीत में अंकित जैन ने कहा कि दीक्षा केवल सांसारिक जीवन का त्याग नहीं, बल्कि मनुष्य जन्म को सार्थक करने और आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प है। बचपन से ही मन में मुनि बनने की भावना थी। 7वीं कक्षा में पढ़ते समय पहली बार यह भाव मन में आया था। 11वीं कक्षा में भी संयम मार्ग पर बढ़ने के लिए पुरुषार्थ किया था लेकिन उस समय संयोग नहीं बना तो प्रतापगढ़ से बीकानेर करने के बाद इंदौर में सीए की पढ़ाई शुरू की। सीए फाइनल परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तभी कोरोना आ गया। इस दौरान फिर से वैराग्य जाग्रत हुआ और दीक्षा लेने की भावना प्रबल हुई। पर उस समय भी संकल्प पूरा नहीं हो सका। आखिरकार चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद संयम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया।

आचार्य विशुद्धसागरजी महाराज के दर्शन से बदला जीवन

एक समय ऐसा भी आया जब लगा कि संसार में रहकर जीवन बिताना चाहिए। जब आचार्य भगवंत विशुद्धसागरजी के दर्शन करने पहुंचे, तो मन में अलग ही भाव जागृत हुआ। 25 अक्टूबर को दिल्ली के लाल किले में दीक्षा ग्रहण करते समय मन में यही प्रमुख भाव रहेगा कि मनुष्य जन्म को सार्थक बनाना है। मेरी भावना यही कि कम से कम भवों में आत्म कल्याण के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। दीक्षा केवल घर-परिवार छोड़ना नहीं, बल्कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानकर मोक्ष मार्ग पर चलने का संकल्प है।

आपदा युवा मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम

माही की गूंज, मंदसौर। राज्य आपदा प्राधिकरण मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार आपदा युवा मित्र प्रशिक्षण समापन के अंतर्गत 125 प्रतिभागियों को आपदा की स्थिति में बचाव एवं राहत कार्यों से संबंधित विभिन्न तकनीकों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान बोट इंजन संचालन, ड्राई रेस्क्यू, हेड टो, चिन टो एवं पेट्रोलिंग के दौरान रेस्क्यू कार्यों के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया गया। प्रशिक्षार्थियों को बताया गया कि बाढ़ एवं जल आपदा के दौरान बोट इंजन का सुरक्षित उपयोग कैसे किया जाता है तथा संकट में फँसे व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए किन बचाव तकनीकों का उपयोग किया जाता है। साथ ही, हेड टो एवं चिन टो तकनीक के माध्यम से पानी में फँसे व्यक्ति को सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। एयर रेस्क्यू एवं ड्राई रेस्क्यू के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों तथा पेट्रोलिंग के दौरान आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य करने के संबंध में भी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य आपदा मित्रों को आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित, प्रभावी एवं त्वरित बचाव कार्य करने के लिए सक्षम बनाना तथा जन-धन की हानि को कम करना रहा। इस सात दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान डिस्ट्रिक्ट कमान्डेंट वीरेंद्र सिंह जादौन, कंपनी कमांडर रब्बी काजी, सदीप भंवर सहित प्रशिक्षक गणों सहित समस्त कार्यालयीन स्टाफ एवं एसडीईआरएफ बल उपस्थित रहा।



माही की गूंज, रतलाम।
इंदौर से मुंबई सेंट्रल जाने वाली अवंतिका सुपरफास्ट एक्सप्रेस में टिकट जांच के दौरान बैटिकट यात्रा कर रहे दंपती ने टीटीई के साथ अभद्रता और हंगामा किया। पुरुष यात्री ने खुद को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी का छोटा भाई और रेलवे में पदस्थ एसपी को जीजा बताकर धौंस जमाई। करीब पांच घंटे तक चले विवाद के बाद दंपति को दाहोद स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया।
घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित होने के बाद मामला सामने आया। सोमवार को प्रतिनिधिमंडल ने सीनियर डीसीएम हिना केवलरमानी से मुलाकात कर कार्रवाई और रेलकर्मियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया।
टीटीई मोहम्मद अरमान की शिकायत के अनुसार घटना 10 अक्टूबर 2026 की रात ट्रेन संख्या 12962 के एस-6 कोच में हुई। अरमान साथी टिकट परीक्षकों बलबीर सिंह राठौर और महेश मालवीय के साथ इंदौर से वडोदरा के बीच ड्यूटी पर थे। कोच में बर्थ नंबर 33 से 38 के बीच टिकट जांच के दौरान समेद्र जैन निवासी देवास नाका इंदौर और उसके साथ महिला यात्री मिली। दोनों का ऑनलाइन वेंटिंग टिकट कन्फर्म नहीं होने के कारण स्वतः निरस्त हो चुका था।
टीटीई ने नियमानुसार इंदौर से वडोदरा तक 750

रुपये किराया और 1000 रुपये जुर्माना मिलाकर कुल 1750 रुपये जमा करने को कहा। इसी बात पर विवाद शुरू हो गया। देवास, उज्जैन, नागदा और रतलाम स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की मदद लेनी पड़ी, लेकिन हंगामा जारी रहा। पूरा घटनाक्रम आरपीएफ जवानों के सामने होता रहा, लेकिन वे दंपति को काबू नहीं कर सके।

सांप्रदायिक टिप्पणी और गालियां देते हुआ कैद

वीडियो में यात्री टीटीई से गाली-गलौज और अभद्रता करते नजर आ रहा है। वह बैज नंबर मांगने के साथ वर्दी उतरवाने और स्टेशन के बाहर मिलने पर जान से मारने की धमकी देता सुनाई देता है। अन्य रेलकर्मियों और सुरक्षा बल के सामने आपत्तिजनक तथा सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप भी लगाया गया है। दूसरी ओर महिला यात्री का कहना था कि उसका पर्स गिर गया था और उसके पास नकद रुपये नहीं थे। उसने ऑनलाइन 1720 रुपये देने की बात कही थी। अरमान का कहना है कि मानवीय आधार पर दोनों को वडोदरा तक अपनी सीट पर बैठकर जाने की पेशकश की थी, लेकिन वे दोनों

बर्थ की पಕ್ಕ्री रसीद मांगने लगे। नियमानुसार किराया और जुर्माना जमा करने से मना कर दिया।

जीआरपी ने नहीं की एफआइआर, चेकिंग स्टाफ में नाराजगी

टीटीई अरमान ने कहा कि शासकीय कार्य में बाधा डालने और जान से मारने की धमकी देने के बावजूद जीआरपी ने केवल बिना टिकट यात्रा का सामान्य

प्रकरण बनाया। इसी बात को लेकर चेकिंग स्टाफ में नाराजगी है। आरोपितों के खिलाफ बीएनएस और रेलवे अधिनियम के तहत नामजद कार्रवाई कराने की मांग की है।

टीटीई के साथ अभद्रता का मामला वीडियो के माध्यम से संज्ञान में आया है। जांच रतलाम जीआरपी थाना प्रभारी सोहनलाल पाटीदार को सौंपी गई है। आरोपितों की पहचान कर जल्द प्रकरण दर्ज किया जाएगा। - हेमंत चौहान, एएसपी जीआरपी इंदौर।

36 पुलिसकर्मियों के तबादले

माही की गूंज, रतलाम।
जिले में प्रशासनिक कसावट और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। रतलाम पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमित कुमार ने एक बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए कुल 36 पुलिसकर्मियों के तबादले कर दिए हैं। इस फेरबदल में पांच निरीक्षक व कार्यवाहक निरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हैं, जबकि आरक्षक और प्रधान आरक्षक स्तर के 31 कर्मचारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कई थाना प्रभारियों के बदले गए प्रभार जारी किए गए तबादला आदेश के अनुसार, रक्षित केंद्र में पदस्थ निरीक्षक मनोज कटारिया को जावरा शहर थाना प्रभारी की कमान सौंपी गई है। वहीं जावरा शहर के वर्तमान थाना प्रभारी दीपक मंडलोई का तबादला सैलाना थाने में कर दिया गया है। सैलाना थाना प्रभारी पंकी आकाश अजनार को सैलाना से हटाकर रक्षित केंद्र (पुलिस लाइन) भेजा गया है।

डीएसबी और पिपलोदा में भी हुआ बदलाव

प्रशासनिक फेरबदल के तहत पिपलोदा थाना प्रभारी रमेश कोली को जिला विशेष शाखा (डीएसबी) की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, अब तक डीएसबी प्रभारी की भूमिका निभा रहे रणजीत सिंगार को पिपलोदा का नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है।
निरीक्षकों के अलावा एएसपी अमित कुमार ने निचले स्तर पर भी कसावट लाते हुए आरक्षक और प्रधान आरक्षक स्तर के 31 कर्मचारियों का तबादला किया है। इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य जिले के थानों में कार्यकुशलता बढ़ाना और पुलिस व्यवस्था को अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाना है।

आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे का प्रशिक्षण

माही की गूंज, शाजापुर।
अंतराष्ट्रीय बालिका दिवस के तहत शाजापुर जिले में कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास शाजापुर द्वारा 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 5 दिवसीय विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस तारतम्य में आज महिला एवं बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में शासकीय एकीकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शाजापुर में जागरूकता गतिविधियों का आयोजन कर बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे का प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। सहायक संचालक सुश्री नीलम चौहान द्वारा कार्यक्रम में बालिकाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत आत्मरक्षा प्रशिक्षण के प्रारंभ करने के उद्देश्य को बताते हुवे बालिकाओं को उनके अधिकार एवं कर्तव्य की जानकारी दी गई। साथ ही सुश्री चोहान द्वारा बालिकाओं को आपातकालीन टोल फ्री नंबर पुलिस विभाग 112, वन स्टॉप सेंटर 181, चाइल्ड हेल्प लाइन 1098, सायबर टोल फ्री नंबर 1930 की जानकारी दी गई एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के बारे में बताते हुए पोक्सो ई-बॉक्स के बारे में बताया गया।
पर्यवेक्षक प्रीति जायसवाल द्वारा बालिकाओं को पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई एवं देवेन्द्र गोठी द्वारा बालिकाओं को बाल अधिकारों की जानकारी देते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन की विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर ट्रेनर सुश्री रानी केवट द्वारा बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाये गए। गोतलब है कि विद्यालय में बालिकाओं को महिला एवं बाल विकास द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत निः शुल्क 1 माह का आत्मरक्षा जूडो- कराटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जनों, अभिभावकों बालिकाओं को बाल विवाह रोकथाम की शपथ दिलवाई गईं।
इस अवसर विद्यालय स्टाफ से श्रीमती चंद्रकांता सौराष्ट्रिया, श्रीमती हेमलता शर्मा, श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव एवं बालिकाएं, अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सुश्री रानी केवट ने किया एवं आभार विद्यालय प्राचार्य सत्यनारायण नायक ने माना।



बैंक खातों से खुलीं 55 लाख की ठगी की कड़ियां

माही की गूंज, रतलाम।
डिजिटल अर्रेस्ट के नाम पर व्यवसायी से 55 लाख रुपये की ठगी के मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। ठगी में आरोपियों के बैंक खातों का उपयोग किया गया था। बैंक लेनदेन की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस हैदराबाद और कर्नाटक तक पहुंची।
करीब 20 लाख रुपये होल्ड करवाए हैं। न्यायालय ने तीनों आरोपितों को जेल भेज दिया है। वहीं, कैमरे के सामने डिजिटल अर्रेस्ट का नाटक कर ठगी करने वालों की तलाश की जा रही है।
एसपी अमित कुमार ने बताया कि कुवैत में मोटर पार्स का व्यवसाय करने वाले व्यवसायी कुछ दिनों से रतलाम में रह रहे थे। 15 सितंबर को उन्हें फोन कर खुद को मुंबई के कोलाबा क्षेत्र का पुलिस अधिकारी बताते वाले व्यक्ति ने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ से जुड़े व्यक्ति से बातचीत में होने का आरोप लगाया।

इसके बाद अलग-अलग नंबरों से फोन कर एफआइआर दर्ज होने की बात कही गई। 16 सितंबर को आरोपितों ने एटीएस में काल ट्रांसफर करने का नाटक किया। वाट्सएप वीडियो काल पर पुलिस की वर्दी पहने व्यक्तिों से बात कराई और सुप्रीम कोर्ट के लेटरहेड पर तैयार दस्तावेज भेजकर कानूनी कार्रवाई का भय दिखाया। जांच और सत्यापन के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में 55 लाख रुपये आरटीजीएस से जमा करवा लिए।

35 लाख के ट्रंजेक्शन से हैदराबाद पहुंची पुलिस

जांच में एक्सिस बैंक के खाते में 35

लाख रुपये पहुंचने की जानकारी मिली। यह खाता श्री वेंकटेश्वरा प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी से संबंधित था। इसके आधार पर टीम हैदराबाद पहुंची और आरोपित तेलंगाना निवासी 47 वर्षीय कोडारी वेंकटेश पुत्र राजन्ना कोडारी को पकड़ने की कार्रवाई की।

5 अक्टूबर को ट्रंजिट रिमांड के दौरान कोर्ट परिसर में वेंकटेश को पकड़ते ही उसके साथियों और वकीलों ने टीम को घेर लिया और उसे छुड़ाकर भाग दिया। हालांकि दूसरी टीम ने कोर्ट परिसर के गेट के पास ही उसे दोबारा पकड़ लिया। बैंक खातों के लेनदेन की जांच में कर्नाटक के धारवाड़ मराठा कॉलोनी निवासी अशोक अनन्या की भूमिका सामने आई।



आरोपी मीर यूसुफ, आरोपी वेंकटेश, आरोपी अशोक

वहीं दूसरे स्तर पर 5 लाख 84 रुपये के लेनदेन के आधार पर हैदराबाद के चार मीनार मदीना नगर निवासी मीर यूसुफ पुत्र मीर आजम को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान, साइबर सेल प्रभारी जीवन बारिया, एसआइ मुकेश यादव, प्रधान आरक्षक रितेश पाटीदार, आरक्षक राहुल पाटीदार, रितेश चौधरी, महिला आरक्षक वर्षा पाटीदार की भूमिका रही।

अमानक खाद्य पदार्थ नमूनों के प्रकरणों में लाइसेंस होंगे निरस्त

विभाग सम्मिलित किए गए हैं। निगमानी दल जिले में आकस्मिक निरीक्षण करते हुए खाद्य पदार्थों की जांच करेगा। बैठक में समीक्षा के दौरान कलेक्टर दिव्यांक सिंह ने निर्देश दिए कि खाद्य पदार्थों की जांच हेतु जिले में चलित लेब भ्रमण करेगी। खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर मोके पर ही जांच रिपोर्ट प्रदान करेगी। कलेक्टर ने जिले में खाद्य पदार्थों के नमूना संग्रहण हेतु ब्लॉक स्तरीय रोस्टर बनाए जाने के निर्देश दिए। जिले में जनभागीदारी अथवा शासन स्तर से अति शीघ्र चलित लेब की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्याम सिंह रावत द्वारा निर्देशों के पालन नहीं करने, आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य नमूने प्राप्त करने में लापरवाही करने के कारण उनके निलंबन हेतु शासन स्तर पर समन्वय बनाते हुए जनजागरूकता शिविर लगाए जाएं एवं खाद्य पदार्थ क्रय, विक्रय एवं निर्मात करने वाले को पूर्ण रूप से स्वच्छता एवं शुद्धता रखने के लिए जागरूक किया जाए, नियमों का पालन ना किए जाने के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किए

जाएगी। बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्याम सिंह रावत द्वारा निर्देशों के पालन नहीं करने, आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य नमूने प्राप्त करने में लापरवाही करने के कारण उनके निलंबन हेतु शासन स्तर पर समन्वय बनाते हुए जनजागरूकता शिविर लगाए जाएं एवं खाद्य पदार्थ क्रय, विक्रय एवं निर्मात करने वाले को पूर्ण रूप से स्वच्छता एवं शुद्धता रखने के लिए जागरूक किया जाए, नियमों का पालन ना किए जाने के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किए

निरस्त करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा जारी किए गए। बैठक में नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र में अशुद्ध खाद्य पदार्थों के क्रय विक्रय की रोकथाम हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्ेय कार्यपालन अधिकारी नगर पंचायत, जनप्रतिनिधोगण के साथ समन्वय बनाते हुए जनजागरूकता शिविर लगाए जाएं एवं खाद्य पदार्थ रखने के लिए जागरूक किया जाए, नियमों का पालन ना किए जाने के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किए

जाने के निर्देश जारी किए गए। खाद्य सुरक्षा को लेकर अब प्रतिमाह कलेक्टर की अध्यक्षता एवं जिला सलाहकार समिती के सदस्यों की उपस्थिति में उक्त बैठक आयोजित की जाएगी। आगामी बैठक 23 नवंबर को कार्यालय कलेक्टर सभागृह में किए जाने के निर्देश दिए गए। जिला सलाहकार समिती के सदस्यों के सुझाव अनुसार बैठक में सतत रूप से जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, अशुद्ध खाद्य पदार्थों के क्रय विक्रय पर रोक हेतु निरंतर कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किए गए।

बांसवाड़ा से शुरू हुई प्रेम कहानी का रतलाम में खौफनाक अंत



माही की गूंज, रतलाम।

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के घाटोल से शुरू हुई प्रेम कहानी का रतलाम में खौफनाक अंत हो गया। 20 वर्षीय प्रथम वर्ष की छात्रा सुनहरी पुत्री नारायण भोगी की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके प्रेमी 20 वर्षीय विकास पुत्र प्रतिपाल यादव को

प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। सुनहरी 9 अक्टूबर को घर से लापता हुई थी। अगले दिन रतलाम में रेलवे ट्रैक किनारे नाले में उसका शव मिला। विकास उसे प्रयागराज ले जाने की बात कहकर स्टेशन क्षेत्र में ले गया और विवाद के बाद गला घोटकर हत्या कर दी। शव नाले में छोड़कर वह प्रयागराज भाग गया।

बांसवाड़ा से रतलाम तक की घटना और शिनाख्त

सुनहरी बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र के बडलिया की रहने वाली थी। विकास भी उसी गांव का निवासी है। वह मूल रूप से प्रयागराज के पास बिजलपुर गांव का रहने वाला है और बांसवाड़ा में परिवार के साथ रहकर मावे की दुकान पर मिठाई बनाने का काम करता था। सुनहरी के लापता होने पर स्वजन ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी और विकास पर उसे साथ ले जाने का संदेह बताया था। 10 अक्टूबर को सुबह 11 से 12 बजे के बीच रतलाम जीआरपी को प्लेटफार्म नंबर-4 से आगे बकरा पुल के पास रेलवे ट्रैक किनारे नाले में शव मिलने की सूचना मिली। जीआरपी ने शव को मेडिकल कॉलेज की मंचूरी में रखवाया। पहचान के लिए तस्वीर आसपास के थानों और जिलों की पुलिस को भेजी गई। बांसवाड़ा पुलिस तक तस्वीर पहुंचने के बाद 12 अक्टूबर को सुनहरी की

पहचान हुई। मंगलवार को उसके स्वजन तीन वाहनों से रतलाम पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद शव उन्हें सौंप दिया गया।

होटल में चार घंटे रुके, फिर स्टेशन की ओर ले गया

बांसवाड़ा पुलिस विकास की तलाश में प्रयागराज पहुंची। वह गांव में नहीं मिला तो तलाशी में शव मिलने की जगह से स्टेशन की ओर करीब 100 मीटर दूर कॉलेज बैग मिला। उसमें किताबें, कपियां और कॉलेज की यूनिफॉर्म थी। राजस्थान पुलिस ने बैग जब्त कर लिया।

मंगलवार को डीएसपी देवेंद्र सिंह टीम के साथ उसे रतलाम लाए और एसपी अमित कुमार को सूचना दी। एफएसएल अधिकारी अतुल मित्तल, राजस्थान पुलिस और जीआरपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। तलाशी में शव मिलने की जगह से स्टेशन की ओर करीब 100 मीटर दूर कॉलेज बैग मिला। उसमें किताबें, कपियां और कॉलेज की यूनिफॉर्म थी। राजस्थान पुलिस ने बैग जब्त कर लिया।

शारीरिक संबंध, विवाद और हत्या का खुलासा

टीम विकास को स्टेशन रोड की मनोहर गली स्थित होटल जय महाकाली ले गईं। रजिस्टर के अनुसार वह 9 अक्टूबर की शाम सुनहरी के साथ कमरा नंबर-2 में रुका था। दोनों करीब चार घंटे बाद वहां से निकले। डीएसपी देवेंद्र सिंह ने बताया कि विकास ने पूछाछछ में होटल में युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने और रेलवे ट्रैक किनारे विवाद के बाद गला घोटकर हत्या करने की बात बताई।

जीआरपी थाना प्रभारी सोहनलाल पाटीदार ने बताया कि विकास युवती को स्टेशन के बाहर से दूसरे रास्ते बकरा पुल की ओर ले गया, ताकि दोनों सीसीटीवी कैमरों में कैद न हों। होटल और घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य जुटा रहे हैं। आरोपित के किसी दूसरी युवती से संबंध होने की जानकारी भी सामने आई है। हत्या की वजह और घटनाक्रम की पुष्टि के लिए जांच जारी है।

अंचल में मां आराधना का दौर जोरों पर, गरबों में थिरक रहे माता रानी के भक्त



माही की गूंज, झाबुआ।

इन दिनों अंचल सहित जिला मुख्यालय पर गरबों की धूम मची हुई है। नवरात के पावन अवसर पर माता भक्त माता रानी की भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। शहर के कई गरबा पांडालों में देर रात तक गरबा प्रेमियों की भीड़ उमड़ रही है। चारों ओर उत्साह, उत्सास और माता की भक्ति का माहौल नजर आ रहा है। शहर के माता जी मंदिरों में अलसुबह काकड़ आरती का दौर भी जारी है। शहर के प्रसिद्ध दक्षिण मुख कालिका माता मंदिर पर भी नवरात के चलते भक्तों का ताता लगा हुआ है। यहां प्रतिदिन सुबह काकड़ आरती का आयोजन हर वर्ष अनुसार किया जा रहा है। माता जी मंदिर प्रांगण में ढलती शाम से लेकर देर रात तक गरबों का आयोजन भी हो रहा है। शहर में मुख्य रूप से राजगढ़ नाका, राजवाड़ा और



बुनियादी स्कूल के गरबा पांडालों में गरबा प्रेमियों की भीड़ अब दिन बढती जा रही है तो अम्बे माता मंदिर प्रांगण के शालीन और सुंदर गरबे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आने वाले दिनों में गरबा पांडालों में खचाखच भीड़ दिखाई देने की संभावना है।

इसके अलावा शहर के लगे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण माता रानी की भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में शोर शराबे से दूर माता रानी की भक्ति का अंदाज ही अलग दिखाई दे रहा है। यहां ग्रामीण छोटे-छोटे पांडाल सजाकर पारंपरिक गरबों का आयोजन कर रहे हैं। जिसमें डीजे की धूमधड़ाक से हटकर माता रानी के भजनों का गायन कर पारंपरिक गरबों का आयोजन किया जा रहा है। आदिवासी भाषा के भजनों पर आदिवासी संस्कृति की छटा बिखरी जा रही

विशेष रूप से महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए झाबुआ पुलिस द्वारा दिशा-निर्देश और एडवाइजरी जारी की गई है। जिले के विभिन्न स्थानों और कॉलोनि यों (जैसे वसंत कॉलोनी) में माता की आरती और पारंपरिक गरबा गीतों के साथ गरबा रातों का उत्साहपूर्वक शुभारंभ हुआ है।

देर रात तक चल रहे पांच जगह गरबों के आयोजन

माही की गूंज, सारणी।

शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ नगर में श्रद्धा और उत्साह के साथ शुरू हुआ घट स्थापना के साथ पांच स्थानों पर गरबा आयोजन शुरू हुआ। गरबा पांडालों में आकर्षक साज सजा के बीच नो दिनों तक मां दुर्गा की आराधना हो रही है। ग्राम के बस स्टैंड स्थित माताजी मंदिर पर सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति के सान्निध्य में कई वर्षों से नवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है। नवरात्रि के प्रथम दिन पंडित पुष्पेंद्र जोशी द्वारा विधि विधान से पूजन, अभिषेक, शिखर पर ध्वजा चढ़ा कर घट स्थापना करवाई। साथ ही भैरवनाथ बस स्टैंड, पीपल चौक, पाटीदार मोहल्ला अंबे माता मंदिर एवं चंद्रशेखर आजाद कालोनी में भी देर रात तक गरबों का आयोजन हो रहा है।



30 किलोमीटर पैदल चलकर भक्तों ने माता को अर्पित की 331 मीटर लंबी चुनरी

माही की गूंज, सेंधवा। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र सीमा पर स्थित बड़ी बिजासन माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सेंधवा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भक्त पैदल चुनरी यात्रा निकालकर और दंडवत करते हुए माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। मंदिर में प्रतिदिन 20 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है।



झोपाली, पीसनावल सहित आठ गांवों के तीन हजार से अधिक श्रद्धालु 331 मीटर लंबी चुनरी लेकर करीब 30 किलोमीटर पैदल चलकर बड़ी बिजासन माता मंदिर पहुंचे। यहां विधि-विधान से माता को चुनरी अर्पित की गई। यात्रा संयोजक चेतन पाटीदार ने बताया कि यह यात्रा का छठा वर्ष था। इसमें महिला, पुरुष, बच्चों और बुजुर्गों सहित तीन हजार से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा में सुसज्जित रथ पर मां दुर्गा की प्रतिमा की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र के राजगढ़ स्थित हनुमान मंदिर से बड़ी बिजासन माता मंदिर तक करीब 50 किलोमीटर लंबी वीर हनुमान पैदल चुनरी यात्रा निकाली गई। इसमें 500 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। राजगढ़, घुड़चाल, झापड़ी पाड़वा, कालापाठ सहित आसपास के गांवों के भक्तों ने यात्रा में भाग लिया। यात्रा संयोजक दिनेश तरोले ने बताया कि हिंदू संस्कृति और धार्मिक आस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह यात्रा निकाली गई। ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए यात्राएं सेंधवा शहर और बायपास तक पहुंचीं। यहां विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने पुष्पवर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। पैदल यात्रियों के लिए जलपान और स्वल्पाहार की व्यवस्था भी की गई।

उधर, पीपलिया गोई निवासी युवा संजय कश्यप करीब 40 किलोमीटर की दंडवत यात्रा कर बड़ी बिजासन माता मंदिर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मंत्रत पूरी होने पर वे दंडवत यात्रा कर माता के दर्शन करने जा रहे हैं। सेंधवा पहुंचने पर विधायक मोटू सोलंकी की टीम ने उनका स्वागत किया।

मध्यप्रदेश आदिवासी विकास परिषद के युवा प्रभाग के जिला अध्यक्ष राहुल सोलंकी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान संजय ने विधायक मोटू सोलंकी की जीत के लिए माता से मंत्रत मांगी थी। किसी कारणवश वे पहले अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाए थे। अब नवरात्रि में दंडवत यात्रा कर वे अपनी मंत्रत पूरी कर रहे हैं। नवरात्रि के दौरान क्षेत्र में धार्मिक यात्राओं और श्रद्धालुओं की बढ़ती भागीदारी से माहौल भक्तिमय बना हुआ है।

सड़क चौड़ीकरण के नाम पर सिर्फ ओटले तोड़े चार दिन की तैयारी, भारी पुलिस बल के बावजूद बड़े अतिक्रमणों पर नहीं हुई कार्रवाई

माही की गूंज, खंडवा।

शहर में तीन पुलिसिया से बड़ाबम, इमलीपुरा होते हुए शिवाजी चौक तक सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाने की तैयारी पिछले चार दिनों से चल रही थी। राजस्व, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग की टीम ने सड़क का सीमांकन कर नजूल भूमि पर पांच से दस फीट तक अतिक्रमण होने की बात कही थी। दुकानों पर निशान लगाए गए और संबंधित लोगों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। प्रशासन की तैयारी देखकर कई लोगों ने स्वयं ही अपने निर्माण हटाना शुरू कर दिए थे। उम्मीद थी कि कार्रवाई के बाद सड़क चौड़ी होगी और शहर को यातायात के लिए एक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा, लेकिन मंगलवार को हुई कार्रवाई में तस्वीर अलग नजर आई।

भारी पुलिस बल, नगर निगम के अधिकारियों-कर्मचारियों और चार जेसीबी मशीनों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, लेकिन यह मुख्य रूप से दुकानों के सामने बने ओटलों और नालियों पर डाले गए स्लैब हटाने तक सीमित रही। जिन दुकानों के हिस्सों को अतिक्रमण की जद में बताया गया था, वहां व्यापक स्तर पर तोड़फोड़ नहीं

हुई। बड़ाबम क्षेत्र में वैशाली जी मार्ट सहित अन्य दुकानदारों को फिलहाल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। वहीं एक मंदिर, एक दरगाह और एक मस्जिद से जुड़े मामलों में कार्रवाई रोक दी गई।

कार्रवाई के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए थे। मौके पर करीब 100 पुलिस जवानों के साथ थाना प्रभारी, पुलिस अधिकारी और नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। नगर निगम के लगभग 100 कर्मचारियों की टीम ने चार जेसीबी मशीनों की मदद से अतिक्रमण हटाने का काम किया। सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर और नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव बारगे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इतने बड़े अमले की मौजूदगी के कारण लोगों को उम्मीद थी कि चिह्नित अतिक्रमण हटाए जाएंगे और सड़क की चौड़ाई बढ़ने से यातायात को राहत मिलेगी, लेकिन कार्रवाई में बड़े निर्माणों के बजाय दुकानों के सामने बने ओटलों और नालियों के ऊपर डाले गए स्लैब ही हटाए गए।

प्रशासन के सीमांकन और सर्वे में नजूल भूमि पर पांच से दस फीट तक अतिक्रमण होने की बात



सामने आई थी। कुछ स्थानों पर पक्के निर्माण भी अतिक्रमण की जद में बताए गए थे। दुकानों पर निशान लगाए जाने से संकेत मिले थे कि कार्रवाई के दौरान दुकानों के आगे बड़े हुए हिस्सों को भी हटाया जाएगा। तीन पुलिसिया से बड़ाबम, इमलीपुरा और शिवाजी चौक तक सड़क चौड़ीकरण की योजना से शहर के अंदर यातायात का दबाव कम होने और लोगों को वैकल्पिक मार्ग मिलने की उम्मीद थी। हालांकि, मंगलवार की कार्रवाई के बाद बड़े अतिक्रमणों पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब देखा होगा कि प्रशासन आगे चिह्नित अतिक्रमणों को हटाने के लिए क्या कदम उठाता है।

जय जोहार अभिवादन के अपमान का आरोप, जयस ने कि कार्रवाई की मांग

माही की गूंज, बड़वानी।

भोपाल के रोशनपुर चौराहे पर आदिवासी छात्र कार्यकर्ताओं के साथ कथित दुर्व्यवहार और 'जय जोहार' अभिवादन के अपमान का मामला सामने आने के बाद जय आदिवासी युवा शक्ति (जयस) ने कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम जापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराए और दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। बड़वानी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन ने जापन प्राप्त किया।

जयस का आरोप है कि 13 अक्टूबर 2026 को भोपाल में गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के मुख्यमंत्री निवास घेराव प्रदर्शन के

दौरान ड्यूटी पर तैनात निरीक्षक स्तर के एक अधिकारी ने छात्र कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की और अशोभनीय गालियां दीं। संगठन के अनुसार, छात्रों को जबरन पुलिस वाहन में बैठाकर हिरासत में लिया गया। जयस ने इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने की मांग की है।

जापन में संगठन ने मांग की है कि घटना से संबंधित वीडियो, निगरानी कैमरों के दृश्य, ड्यूटी रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जाए। जांच के आधार पर संबंधित अधिकारी की पहचान कर दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सहित अन्य लागू कानूनी

प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए। साथ ही हिरासत में लिए गए छात्रों की कार्यकर्ताओं के साथ हुए व्यवहार और हिरासत की



कानूनी वैधता की जांच कर उसकी रिपोर्ट लिखित रूप में उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है।

जयस कार्यकर्ताओं ने मामले में 24 घंटे के भीतर प्रारंभिक कार्रवाई की अपेक्षा जताई है। संगठन ने चेतावनी दी कि निर्धारित समय में

उचित कदम नहीं उठाए गए तो वह मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग और न्यायालय का रुख करेंगे। संगठन ने मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग दोहराई है।

विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच संवाद भी जरूरी

पिछले हफ्ते, जहां नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे करने की खुशियां मनाई- पहले बतौर गुजरात का मुख्यमंत्री रहते और पिछले 12 सालों से प्रधानमंत्री के रूप में- वहीं राहुल गांधी और उनकी राजनीति भी वक्त के साथ परिपक्व हुई। मार्का बन चुकी अपनी सफेद टी-शर्ट और खाकी कार्गो पैंट पहने, कांग्रेस नेता उन पीले बैरिकेड्स पर चढ़ गए जिनसे दिल्ली का हर निवासी भली-भांति वाकिफ है और उन्होंने तिरंगा लहराया। उनकी बहन प्रियंका उनके बगल में खड़ी थीं और उन्होंने भी यही किया। एक दिन बाद, वह सड़क पर लेट गईं और सीने पर संविधान की एक प्रति थी; पुलिस को उन्हें उठाने को ललकाया। उसने वही किया।

भारतीय राजनीति में पिछला सप्ताह उन हफ्तों में से एक रहा, जब तरह-तरह की गहमागहमी सुर्खियों में छई और बनी रह गई। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को गत शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मार्च करने की इजाजत नहीं दी। दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज ने भारतीय युवा कांग्रेस से, जिसने विरोध प्रदर्शन करने की अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी, कहा, 'इतनी जल्दी क्या है?' सुनवाई सोमवार यानी आज होगी।

सीजेपी ने कहा है कि वह फिर भी आगे बढ़ेगी और जानना चाहती है कि उसे विरोध करने के हक से क्यों वंचित किया जा रहा है, जोकि संविधान प्रदत्त एक अधिकार है- अनुच्छेद 19(1)(ए) आपको शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 19(1)(सी)

नागरिकों को असहमति जताने, रैलियां करने और सामूहिक रूप से मुद्दे उठाने की अनुमति देता है, जबकि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जिसकी व्याख्या बृहद रूप से शांतिपूर्वक और सम्मान के साथ अपनी शिकायतें व्यक्त करने के अधिकार के रूप में की गई है।

दिल्ली को एक किले में बदला गया। राजधानी की सुरक्षा के लिए लगभग 23,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। वाराणसी से दिल्ली आने वाली रेलगाड़ियों सहित कई रेलगाड़ियां रद्द कर दी गईं। मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। सीमाएं सील कर दी गईं।

सवाल यह है कि केंद्र सरकार अचानक इतनी बौखलाई हुई क्यों दिख रही है? सत्ता की बागडोर मजबूती से उनके हाथ में है और अगले ढाई साल तक कोई उन्हें हिला भी नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ की कहीं जाने की संभावना नहीं है-भले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कर लें, फिर भी योगी की बीजेपी को हराना मुश्किल होगा। जहां तक पंजाब की बात है, चुनावी लिहाज से यह बहुत छोटा राज्य है, यहां मात्र 13 लोकसभा सीटें हैं, हालांकि पंजाब का जोश लोगों के मूड का एक शानदार संकेत अवश्य बना हुआ है।

दिल्ली के हुक्मरानों में फैली इस घबराहट का एक शब्द में जवाब है-नौकरियां। सरकार को अच्छी तरह पता है कि इस मामले में वह कमजोर स्थिति में है, शायद सत्ता में अपने 12 सालों में पहली बार, क्योंकि देश के युवा पूरी तरह से उनके साथ नहीं हैं। भारत की चर्चित और ख्यात-कुख्यात 'जेन-जी' पीढ़ी के आंकड़ों को फिर से दोहराए तो देश की कुल



नोट पेपर लीक होना और परिणामतः उम्मीदों से भरे भारत के 20 साल के करीब के युवाओं को जो सदमा लगा, वह शायद इस तेजी से स्वरूप बदलते इस देश के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ - एक ऐसा समय जब सब कुछ बेकार लगने लगा है; और भारत के चोटी के कॉलेजों में पढ़ना काफी नहीं रह गया, यहां तक कि आपके लिए यह धौंस देना भी कि 'तुम जानते नहीं भरे पिता कौन हैं', लिफ्टभावी हो गया है।

हाबिदा की 27 फीसदी हिस्सा- यानी हर चौथा व्यक्ति - 15 से 29 साल की उम्र का है; 52 फीसदी आबादी यानी हर दूसरा व्यक्ति 30 साल से कम उम्र का है; और 140 करोड़ की आबादी में से 65 प्रतिशत लोग 35 साल से कम उम्र के हैं; जब अमेरिका और कनाडा आपके लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं - वे आपकी कॉलेज शिक्षा से उगाहे जाने वाले पैसे तो चाहते हैं, लेकिन आपको नौकरी देना नहीं चाहते; यहां तक कि अब एच-1बी वीजा मिलना भी मुश्किल हो गया है।

इतना ही नहीं, जैसे-जैसे सोशल मीडिया अपना एक अलग जगत बना रहा है और खबरें तुरंत मिल जाती हैं, टीवी एंकर अपनी प्रसंगिकता कम होती पा रहे हैं। रात के 9 बजने से पूर्व देशभर को पहले ही वह पता पता चल चुका होता है, जो आप सोचते हैं कि लोग जानना चाहेंगे। लाखों डिजिटल क्रिएटर्स के हाथ में व्यंग्य, तंज और कटाक्ष रूपी हथियार हैं और उन्होंने चुनिंदा प्राइम-टाइम इन्फ्लुएंसर्स की जगह ले ली है। बताने की जरूरत नहीं कि संविधान और उसके सभी अनुच्छेद भी अब इस्टाग्राम पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कह दिया है कि 'संपूर्ण शटडाउन' इसका समाधान नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही मणिपुर का अपना दौर रद्द कर चुके हैं। इस उथल-पुथल भरे माहौल में कांग्रेस पार्टी और सीजेपी को अपनी-अपनी आवाज मिली है। कम से कम सीजेपी से जुड़े लोग तो 20 और 30 की उम्र के हैं

- तो फिर 56 साल के राहुल गांधी के पास क्या बहाना है? सिवाय इसके कि एलन मस्क द्वारा भारत में कथित 'क्रोनी कैपिटलिज्म' (अपने खासमखास सेठों को फायदा पहुंचाने वाला पूंजीवाद) पर किए गए तंजनुमा ट्वीट के जवाब ('दूसरे एक व्यक्ति के बारे में पता चलने तक इंतजार करें') ने सरकार को बेचैन कर दिया-इस आलोचना का जवाब देने के लिए सरकार ने अपने सबसे शालीन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारा है।

कांग्रेस पार्टी ने स्पष्टतः अपनी राजनीतिक रणनीति बदल ली है। बीजेपी की नाकामियों पर हमला करने के बजाय, अब वह उसकी कामयाबियों पर सवाल उठा रही है - 7.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर को चुनौती देकर; बढ़ते बुनियादी ढांचे, खासकर सड़कों पर सवाल उठाना; यह सवाल उठाना कि चीन के शी जिनपिंग को ब्रिक्स सम्मेलन में बुलाया ही क्यों गया, यह देखकर भी कि वह भारत का सबसे बड़ा विरोधी बना हुआ है; और 'वोट चोरी' का मुद्दा उठाकर, कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग में मतभेद इसका पक्का सबूत है कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे से छेड़छाड़ की जा रही है।

बेशक, कांग्रेस और सीजेपी को शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार है। 'ज्ञानेश, बस बहुत हो गया भाई' लिखे हुए प्लेकार्डों से कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं होने वाली। सरकार को यह स्वीकार करना चाहिए कि लोगों को असहमत होने, विरोध करने और अलग राय रखने का अधिकार है। वहीं, अपनी ओर से कांग्रेस और सीजेपी को यह यकीनी बनाना होगा कि उनका विरोध शांतिपूर्ण रहे। दोनों पक्षों को बीच की राह निकालने के लिए एक-दूसरे से बात करनी चाहिए और बातचीत की डोर को फिर से बहाल करना चाहिए, जो बहुत पहले टूट चुकी है। आखिरकार, दोनों पक्षों को यह अहसास करना चाहिए कि हमारे पास एक ही देश है व एक ही चुनाव है जो हर पांच साल में हमारे मतदान जीवन को तय करता है। उन 13 करोड़ वोटों के नाम फिर से मतदाता सूची में शामिल किए जाएं, जो किसी न किसी वजह से हटा दिए गए थे और वे अपने बुनियादी वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने अगले 'मन की बात' कार्यक्रम में हरि में संबोधित करें व भरोसा दिलाएं कि हम सब एक ही परिधि में आते हैं - चाहे हम भाजपा, कांग्रेस, आप, समाजवादी पार्टी या नोटा को वोट देते हों।

नागरिकों को अपना रोष ज़ाहिर करने का जायज माध्यम मिलना चाहिए; हम सभी अतीत में इसे कुचलने के बुरे नतीजों से अच्छी तरह वाकिफ हैं।

दो हजार वाली सस्ती शराब की पेटी शंभु को दी मुझे क्यों नहीं दी की बात पर दो अवैध शराब विक्रेताओं के बीच हुआ विवाद

टेके की शराब दुकान पर पदस्थ सेल्समेन भी बने विवाद का कारण

माही की गूंज, खवासा।

पुलिस के संरक्षण के साथ शराब माफियाओं, अवैध विक्रेताओं, गंजेड़ियों, मनचलो आदि के कारण शांतिप्रिय कहे जाने वाले खवासा को विवादों एवं अपराधों का गढ़ बनाया जा रहा है। जो कहीं न कहीं क्षेत्र की प्रतिष्ठा को ही खराब कर रहा है।

करीब एक वर्ष पूर्व बाजना मार्ग स्थित ढाबा संचालक एवं अवैध शराब विक्रेता जितेंद्र गेहलोत के साथ दो भाइयों ने नशा कर जानलेवा हमला किया था। यह तो गनीमत रही कि, जितेंद्र बच गया। वहीं पिछले दिनों मामूली बात पर ही अवैध शराब विक्रेता तथा गंजेड़ी दोस्तों के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना हुआ कि, एक बड़ा माहौल बना दिया। इस बात को कुछ ही दिन हुए कि, एक ही बात को लेकर दो दिनों तक दो अवैध शराब विक्रेता एवं उसके दोनों पुत्रों के मध्य हुआ विवाद भी अब गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है।

मामला यू सामने आ रहा है कि, शंभु नाम का व्यक्ति अपने पुत्र के साथ पुराना पशु चिकित्सालय के पास, ग्रिट मार्ग बामनिया बाय-पास व बाजना मार्ग पर मिशन स्कूल के समीप तीन अवैध शराब दुकान का संचालन करता है। बताया जाता है कि, शम्भु अपने अवैध व्यवसाय में शराब दुकान के मैनेजर एवं सेल्समैन से अपना व्यवहार इतना अच्छा रखता है कि, जब भी शराब टेकेदार द्वारा कम भाव की शराब या टेकेदार द्वारा कम भाव करने की जानकारी सर्वप्रथम शम्भु को सेल्समैन द्वारा मिल जाती है। और उस फायदे का लाभ समय पर शम्भु ले लेता है।

इसी कड़ी में क्षेत्र में वर्तमान में सर्वाधिक बियर विक्री में माउंट, लिजेन्ड बियर बिकती है। जिसका टीन पेटी का वर्तमान भाव 24 सौ रुपए पेटी बताया जा रहा है। वहीं एक बोल्ट नाम से बियर आती है उसका भाव 4 सौ से 5 सौ रुपए कम में टेकेदार अवैध शराब विक्रेताओं को देता है। वहीं शनिवार को सामने आया कि, जब शम्भु सुबह अंग्रेजी कंपोजिट शराब दुकान पर शराब की पेटी लेने गया तो सेल्समैन ने सस्ते भाव की बोल्ट बियर भी आ गई है बताया और शम्भु बोल्ट बीयर 2 हजार रुपए प्रति पेटी के भाव से 4 सौ रुपए फायदे वाली यह बीयर की पेटिये ले गया।

वहीं विवाद का कारण यह रहा कि, पूर्व उपसरपंच कमलेश या उसका पुत्र चिराग जब सुबह शराब की पेटी लेने गया तो सेल्समैन ने 4 सौ रुपए फायदे वाली आई बियर की पेटीयो के बारे में जानकारी नहीं दी। जानकारी रखने वाले बताते हैं कि, पूर्व उपसरपंच ग्रिट मार्ग पर एक अन्य बहदुर नाम का शराब विक्रेता के यहां पर बैठा था कि, शम्भु के कर्मचारी ग्रिट मार्ग स्थित शम्भु के अवैध शराब अड्डे पर स्कूटी पर लाद खुले में फायदे वाली शराब की पेटिया ले जा रहा था जो देखा। तत्पश्चात पूर्व उपसरपंच सीधे अंग्रेजी शराब की कंपोजिट दुकान के



सेल्समैन को फोन कर कहा, शम्भु को 2 हजार वाली शराब की पेटी दी लेकिन मुझे क्यों नहीं दी...? की बात के साथ सेल्समैन के साथ मुंह जुबानी फोन पर हुई। वहीं बताया जा रहा है कि, अंग्रेजी कंपोजिट शराब दुकान पर पदस्थ कोई यादव व चुन्नू नाम के सेल्समैन ने अवैध शराब विक्रेता कमलेश द्वारा शम्भु को सस्ती वाली शराब दी और मुझे क्यों नहीं दी वाली बात के साथ दो बात बढ़ा-चढ़ा कर शम्भु को कह दी। सेल्समैन से मिली जानकारी पर तामसी प्रवृत्ति के साथ तीन अड्डे संचालित करने वाले शम्भु

ने कमलेश को फोन लगाकर गाली गुला के साथ सेल्समैन को नाम लेकर कमलेश को धमकाने का प्रयास किया कि, तू मेरा नाम लेकर बोल्ट बियर लाया ऐसा तूने क्यों कहा। मैं तेरी दुकान पर आकर तुझे सबक सिखाता हूँ धमकाया।

उक्त धमकी की बात जब कमलेश के पुत्र को लगी तो मेरे पिता को गाली देने व धमकाने वाला शम्भु कौन होता है? कहते हुए बाजना मार्ग स्थित शम्भु की दुकान पर अन्य द्वारा समझाने के बावजूद एक से अधिक बार पहुंचा। जिस पर शम्भु का पुत्र अर्जुन एवं कर्मचारी ने कमलेश के पुत्र को लड़व हाथ से मारा। उक्त जानकारी जब कमलेश को लगी तो वह भी पहुंचा

और आमने-सामने हाथा पाई होने के बाद जब समझाकर कमलेश व चिराग को ले जाया जा रहा था उस समय बाइक के पीछे शम्भु एवं पुत्र ने बाप-बेटे को पीछे से भी झापट मारी। बात वहीं खत्म नहीं होकर कमलेश के पुत्र ने शम्भु के पुत्र को मारने की ठानी और रविवार सुबह जब शम्भु का पुत्र अर्जुन शराब की पेटिया स्कूटी पर लेकर पुराने पशु चिकित्सालय के पास अपने शराब के अड्डे पर आ रहा था कि, उस दौरान कमलेश के पुत्र चिराग ने अर्जुन को शराब की पेटियो से लड़ी स्कूटी के साथ मारना शुरू कर दिया। उक्त

घटना के समय चौकी पर पदस्थ एक हेडसाब भी सामने ही खड़े थे और पूरी घटना को देखा। लेकिन न ही विवाद करने वाले युवकों को पकड़ा और न ही शराब से लड़ी स्कूटी को जप्त करने की मशकत की।

विवाद बढ़ते देख लोगों ने हड़वाया। जिसके बाद शम्भु एवं पुत्र अर्जुन, चिराग के विरुद्ध एमएलसी के साथ क्रॉस रिपोर्ट दर्ज करने की बात कर दोनों को हवालात में डाल दिया।

इसी बीच चौकी पर एक पक्ष कहता नजर आया कि, शम्भु तीन काउंटर अवैध शराब विक्री के चलाता है। वहीं दूसरा पक्ष कहता नजर आया कि, कमलेश व उसके पुत्र में जोर हो तो जितने अवैध काउंटर शराब के चलाना हो उतने चलाएंगे। उक्त चर्चाएं पुलिस चौकी में पुलिस के समक्ष होती रही। लेकिन शराब माफियाओं के हाथों अपनी खाकी वर्दी को गिरवी रखने वाली पुलिस ने इन किसी भी शराब के अड्डों पर जाकर विवाद की मूल जड़ रही अवैध शराब को पकड़ने की कोई कार्रवाई नहीं की। न ही आगे से अवैध शराब के अड्डे बंद करने की बात कही। सिर्फ किया तो दोनों ने सुलह करवाकर घर भेज दिया और शराब बेचने की अनधिकृत परमिशन के साथ विवाद को खत्म करने का कार्य किया। लेकिन साहब यह विवाद जब तक यह अवैध शराब के अड्डे खवासा में संचालित होते रहेंगे यह तामसी प्रवृत्ति वाले अपनी अवैध कमाई की रोब के साथ खवासा एवं क्षेत्र का माहौल वार हो या त्योंहार हो हर समय बिगाड़ते ही देखे जाएंगे।

आज निकाली जाएगी विशाल चुनरी यात्रा



माही की गूंज, आम्बुआ।

क्षेत्र में इन दिनों शारदीय नवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न अयोजन संपन्न किए जा रहे हैं, प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी अंबे माता को चुनरी अर्पित की जाना है जिसकी संपूर्ण तैयारियां पूरी हो चुकी है आज 15 अक्टूबर को विशाल चुनरी यात्रा निकाली जाएगी।

आम्बुआ कस्बे में इन दिनों शारदीय नवरात्र की धूम धाम बनी हुई है, मंदिरों तथा गरबा पांडालों में विराजमान मां की मूर्तियों की पूजा अर्चना आदि की जा रही है, कस्बे विगत वर्षों से एक विशाल चुनरी यात्रा निकाली जाती रही है उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी अंबे माता को चुनरी अर्पित की जा रही है। आज लगभग तीन बजे श्रीराम मंदिर प्रांगण से एक विशाल चुनरी यात्रा निकाली जा कर लगभग दो किलोमीटर दूर स्थित मां अंबे माता मंदिर टेकरी पर जा कर माता जी को कस्बे के समस्त हिन्दू सनातन धर्मावलंबियों की ओर से विशाल चुनरी अर्पित की जाएगी। कार्य क्रम के लिए कस्बे में उत्साह का माहौल बना हुआ है। आयोजन समिति ने अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो कर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दें।

विधायक ने विद्युत डीपी का किया उद्घाटन, किसानों को मिलेगी राहत



माही की गूंज, आम्बुआ।

जोबट विधानसभा क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने और ग्रामीणों एवं किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने

की दिशा में विधायक सेना महेश पटेल ने छोटा इंटारा ग्राम पंचायत के डुडवा फलिया में विधायक निधि से 6 लाख 7 हजार रुपये की लागत से स्थापित विद्युत डीपी का उद्घाटन किया। विद्युत डीपी की स्थापना से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने में

मदद मिलेगी। साथ ही स्थानीय किसानों को कृषि कार्यों और सिंचाई के लिए बिजली सुविधा मिलने से लाभ होने की उम्मीद है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या का सीधा असर किसानों की खेती और आमजन के दैनिक जीवन पर पड़ता है। समय पर बिजली उपलब्ध नहीं होने से किसानों को खेतों में सिंचाई करने में परेशानी होती है, वहीं ग्रामीण परिवारों को भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में डुडवा फलिया में 6 लाख 7 हजार रुपये की लागत से विद्युत डीपी की स्थापना क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नई विद्युत डीपी से क्षेत्र में बिजली समस्याओं का सुचारु बनाने में सहायता मिलेगी। इससे किसानों को खेतों में सिंचाई करने, फसलों की बेहतर देखभाल करने और कृषि कार्य समय पर पूरा करने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। वहीं ग्रामीण परिवारों को भी घरेलू

कार्यों, बच्चों की पढ़ाई और अन्य आवश्यक गतिविधियों के लिए बेहतर बिजली सुविधा मिल सकेगी।

किसानों और ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता : सेना महेश पटेल

इस अवसर पर विधायक सेना महेश पटेल ने कहा कि जोबट विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों और किसानों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। किसानों को खेती और सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिले तथा ग्रामीणों को बिजली संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। छोटा इंटारा ग्राम पंचायत के डुडवा फलिया में विधायक निधि से 6 लाख 7 हजार रुपये की लागत से विद्युत डीपी स्थापित की गई है। इससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने और किसानों को कृषि कार्यों में सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। विधायक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तभी संभव है, जब लोगों को बिजली, सड़क, सहित अन्य जरूरी

सुविधाएं उपलब्ध हों। किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर बिजली सुविधा मिलने से खेती-किसानों के कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जोबट विधानसभा क्षेत्र के गांवों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए आगे भी प्रयास जारी रहेंगे।

वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता एवं ग्रामीण रहे उपस्थित

विद्युत डीपी के उद्घाटन अवसर पर उदयगढ़-बोरझाड़ मंडल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. राजेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बिजली ग्रामीणों की भी सहायता है। ग्रामीणों ने क्षेत्र में विद्युत सुविधा के विस्तार को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की। विद्युत डीपी की स्थापना से किसानों को खेती-किसानी और सिंचाई के कार्यों में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

डुडवा फलिया में विद्युत डीपी का उद्घाटन क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि नई विद्युत डीपी से बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा और किसानों को खेती-किसानी के कार्यों में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी।

गांजे की अवैध खेती पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

दो खेतों में मिली गांजे की फसल, दो आरोपी अभिरक्षा में



माही की गूंज, आम्बुआ।

मुख्यमंत्री नशा मुक्ति अभियान के तहत आलीराजपुर पुलिस ने आम्बुआ थाना क्षेत्र में अवैध गांजे की खेती के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। पुलिस के अनुसार, संयुक्त कार्रवाई के दौरान दो खेतों से कुल 2,040 गांजे के पौधे जब्त किए गए, जिनका कुल वजन 2,079 किलोग्राम बताया गया है। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत एक करोड़



दो खेतों में मिली गांजे की फसल

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पहले खेत से 1,110 पौधे, जिनका कुल वजन 1,530 किलोग्राम बताया गया है, जब्त किए गए। इस मामले में छोटा इंटारा निवासी मुकाम चौहान (44), पुलिस ने

रलिया चौहान, को अभिरक्षा में लिया गया। पुलिस ने अपराध क्रमांक 299/26 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 में प्रकरण दर्ज किया है।

वहीं, दूसरे खेत से 930 पौधे, जिनका कुल वजन 549 किलोग्राम बताया गया है, जब्त किए गए। इस मामले में छोटा इंटारा निवासी जगन (50), पिता गुलसिंह, को अभिरक्षा में लिया गया। पुलिस ने अपराध क्रमांक 300/26 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 में प्रकरण दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, दोनों मामलों में कुल 2,040 पौधे जब्त किए गए, जिनका कुल वजन 2,079 किलोग्राम यानी 20 किलो 79 किलोग्राम है। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत एक करोड़ रुपये बताई गई है।

चार थानों की पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई

यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्योति उमठ बघेल तथा जोबट एसडीओपी आशुतोष पटेल के पर्यवेक्षण में की गई। संयुक्त टीम में आम्बुआ थाना प्रभारी उपनिरीक्षक मोहन डावर, जोबट थाना प्रभारी निरीक्षक विजय वास्करले, उदयगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक ब्रजभूषण हीरवे, आजादनगर थाना पुलिस तथा संबंधित पुलिसकर्मियों और साइबर पुलिस टीम की भूमिका रही।

अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान जारी

आलीराजपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री नशा मुक्ति अभियान के तहत जिले में अवैध मादक पदार्थों की खेती, संग्रहण, परिवहन और विक्री के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इस कार्रवाई को जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की महत्वपूर्ण कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।

डकैतों को बचाने के लिए पुलिस ने 7 वर्ष तक दबाई फाइल

माही की गूंज, धार। जिले में खाकी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। धरमपुरी थाने की पुलिस ने डकैती जैसे संगीन मामले में अपराधियों को बचाने के लिए जो खेल खेला, उसने अदालत को भी सन्न कर दिया। कोर्ट ने इस पूरी कार्रवाई को पुलिस विभाग के दामन पर एक बड़ा कलंक करार दिया है और तत्कालीन जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। यह पूरा मामला 16 दिसंबर 2017 की रात का है, जब टक्काई गांव में व्यापारी शंकरलाल जायसवाल के घर पर 10-12 सशस्त्र डकैतों ने धावा बोला था और नकदी व जेवराल लूट ले गए थे।

इस तरह जांच की दिशा भटकवाई गई

मामले की जांच कर रहे तत्कालीन थाना प्रभारी कुशलसिंह रावत और विवेक एएसआई प्रकाश सरोदे ने इस गंभीर वारदात को महज 4 आरोपियों तक सीमित कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 31 मार्च 2018 को तैयार की गई खान्सा रिपोर्ट को थाने में ही दबाकर रखा गया और इसे 7 साल बाद 26 अप्रैल 2025 को अदालत में पेश किया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि विवेक ने एफआईआर की भाषा को ज्यों का त्यों केस डायरी में उतार दिया, जबकि मौके पर मारपीट का शिकार हुई व्यापारी की पत्नी तक के बयान दर्ज नहीं किए गए। यहां तक कि डॉक्टर की एक्स-रे की सलाह को भी नजरअंदाज कर दिया गया।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी और आगे की कार्रवाई

धरमपुरी के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विवेक जैन को अदालत ने इस मामले में तीखी टिप्पणी करते हुए लिखा कि यह जांच किसी कानूनी प्रावधान से नहीं बल्कि पीएसपीसी और केआरपीसी के तहत चलाई गई प्रतीत होती है। अदालत ने एसपी धार को पत्र लिखकर एक महर्न के भीतर दोनों पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि यदि विभाग कार्रवाई नहीं करता है, तो अदालत खुद एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। साथ ही, अब इस मामले में नए विवेक की नियुक्ति कर हर 30 दिन में प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला अब भी मनरेगा के चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पा रहा, उधर अन्य जिलों में वीबी जीरामजी नई स्कीम में काम मिलना शुरू

मनरेगा के पुराने भुगतान और नई योजना में तकनीकी दिक्कतों को लेकर सरपंच हो रहे परेशान

चार साल से जीत कर सरपंच की गद्दी पर बैठने के बावजूद, बाजारों में चोरों की तरह निकलना पड़ रहा

माही की गूंज, झाबुआ। मुजमिल मंसुरी

पुरानी मनरेगा योजना जिसे मूल रूप से नरेगा (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के नाम से जाना जाता था। भारत सरकार की एक ऐतिहासिक और दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजनाओं में से यह एक योजना थी। यह कानून भारतीय संसद द्वारा 5 सितंबर, 2005 को पास किया गया था। इसे आधिकारिक तौर पर 2 फरवरी, 2006 को देश के सबसे पिछड़े 200 जिलों में शुरू किया गया था। 1 अप्रैल, 2008 तक इसे पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू कर दिया गया। 2 अक्टूबर, 2009 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर इसका नाम बदलकर 'नरेगा' (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) से 'मनरेगा' (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) कर दिया गया था।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं यह थी कि, इस योजना में ग्रामीण भारत के प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम की कानूनी गारंटी देती है। यदि कोई व्यक्ति काम के लिए आवेदन करता है और सरकार उसे 15 दिनों के भीतर काम देने में असमर्थ रहती है, तो सरकार को उसे घर बैठे बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। इस योजना में नियम के अनुसार रोजगार श्रमिक के गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में ही काम दिया जाना चाहिए। यदि काम इससे दूर है, तो अतिरिक्त यात्रा भत्ता मिलने का प्रावधान भी इस योजना के नियमों में था। इस योजना में कानूनी तौर पर कम से कम एक तिहाई (33 प्रतिशत) रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया था।

जब 2005 में इस योजना को बनाकर

जमीन पर उतारा गया था तब इसके उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना देना, गांवों से शहरों की तरफ होने वाले पलायन को रोकना, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, जैसे तालाबों की खुदाई, कुआं निर्माण, पौधारोपण, नहरों की मरम्मत और सड़कों का निर्माण करना आदि शामिल था। यह योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई।

इसके तहत अकुशल मजदूरी का 100 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार ने उठाया। जबकि सामग्री की लागत में केंद्र और राज्य का अनुपात 75/25 होता रहा।

सरकार की 2005 में शुरू की गई यह योजना लगातार अपने बदलते स्वरूप में चलती रही। शुरूआती दौर में इस योजना ने कामयाबी के नए आयाम गढ़े। गरीब और ग्रामीण लोगों को इससे फायदा भी पहुंचता दिखाई दिया, लेकिन धीरे-धीरे इस योजना की कार्यप्रणाली सुस्त पड़ती दिखाई दी और इस योजना में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला देखने को मिला। सरकार ने यह योजना ग्रामीणों को गरीबों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शुरू की थी। लेकिन देखते ही देखते इस योजना में गरीबों का भला कम और भ्रष्ट तंत्र के वारे न्यारे होते दिखाई दिए। तंत्र की लापरवाही और भ्रष्टाचार का आलम यह रहा कि, इस योजना में तंत्र में बैठे अधिकारियों ने हथेली को दिल्ली और अंगुठे को कुतुब मिनार तक दिखा दिया। मतलब कागजों पर बड़े-बड़े निर्माण और तालाब बने लेकिन जमीनी की हकीकत सिर्फ नजर आई। एक दौर वह भी देखने को मिला जब अखबारों के पन्ने सिर्फ और सिर्फ इस योजना के भ्रष्टाचार से पट्टे दिखाई देने लगे थे।

हालांकि यह योजना 2025 तक भी इसी तरह के भ्रष्टाचार में उलझती दिखाई दी



है। इस योजना के तहत जहां ग्रामीण श्रमिकों से काम लिया जाना था वहां भ्रष्टांत्र ने मशीनों का भर पड़े उपयोग किया और गरीबों का हक मार दिया। रातो-रात मशीनों से इस योजना में तालाब बना दिए। रातो-रात स्टॉप डेम मशीनों का उपयोग कर बना दिए गए। इस योजना में होने वाला श्रमिकों का हर एक काम भ्रष्ट तंत्र ने मशीनों से करवा डाला। नतीजा यह निकलकर सामने आया कि, अधिकारियों ने भ्रष्टाचार कर अपनी जेबे तो गरम कर ली लेकिन गरीब ग्रामीणों का दोहरा नुकसान कर डाला। एक तरफ तो ग्रामीण मजदूर, मजदूरी से गए और दूसरी तरफ योजना में मशीनों से किए कार्य भी महज कुछ ही समय में भ्रष्टाचार को उजागर करने लगे।

मशीनों से बने तालाब महज एक या दो बारिशों में बह गए। सड़कें महज कुछ महीनों में ही उखड़कर धूल हो गई तो स्टॉप डेम भी अपनी जगह छोड़ गए।

ऐसा नहीं है कि, इस योजना का हर काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, लेकिन इस योजना में जो काम जमीन पर उतरे और जिन ग्रामीणों को इस योजना में श्रम करने का मौका मिला उनकी हालत भी कुछ ठीक नहीं रही। इस योजना में भुगतान को लेकर हमेशा से ही संघर्ष वाली स्थिति

देखने को मिलती रही है। कहीं निर्माण कार्यों का भुगतान अटकता रहा है तो कहीं मजदूरों की मजदूरी। हालांकि देर से इन् इन सभी का भुगतान हुआ, लेकिन यह योजना समय से कई गुना पीछे दिखाई देने लगी। इस योजना में निर्माण सामग्री और मजदूरी



नए नाम के साथ इसे 2026 में फिर से लागू कर दिया है। मनरेगा योजना में छोटे-मोटे परिवर्तन कर भाजपा की केंद्र सरकार ने से 1 जुलाई 2026 को नया बदलाव करते हुए वीबी-जी राम जी (भारत-रोजगार और आजीविका मिशन के लिए

गारंटी) के नाम से लागू करते हुए मनरेगा को प्रतिस्थापित किया। जिसके अंतर्गत रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। बाकी वही मनरेगा वाली स्थिति है जैसे काम ना मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता, काम घर से 5 किलोमीटर की सीमा में और इसमें भी वही 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण। हालांकि इसमें राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी फ्लोर लगभग

300 रुपए प्रतिदिन निर्धारित है। लेकिन इस महंगाई के दौर में यह बहुत ही कम है। जबकि अन्य असरकारी कामों में मजदूरों को यही मजदूरी लगभग दोगुना मिलती दिखाई दे रही है। इस नई योजना में सामान्य राज्यों के लिए केन्द्र और राज्य का अनुपात जरूर बढ़कर 60-40 का हो गया है। हां यह जरूर है कि इस योजना में कुल 375 प्रकार के कार्य शामिल किए गए हैं। जो विकसित ग्राम पंचायत योजना और ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित होतें हैं।

इस नई वीबी जी-राम जी योजना के

कार्य लगभग सभी जगहों शुरू हो चुके हैं। प्रदेश के लगभग हर जिले में इस योजना का लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन स्थानीय स्तर पर अगर झाबुआ जिले की बात करें तो यहां की स्थिति ठीक इसके विपरीत दिखाई देती नजर आ रही है। यहां पर ग्रामीण क्षेत्रों के सरपंच अब भी पुरानी मनरेगा योजना के भुगतान को लेकर परेशान हैं। पिछले 2-3 वर्षों से उन्हें व उनकी पंचायत को मनरेगा

योजना का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस रूके भुगतान की रकम करोड़ों में है। सरपंचों के अनुसार उन्हें निर्वाचित हुए लगभग चार साल गुजर चुके हैं। मगर उनकी पंचायतों में न तो नए काम दिए जा रहे हैं और ना ही पुराने कामों का भुगतान किया जा रहा है। स्थिति यह हो चली है कि, अब सरपंचों व सचिवों को बाजारों में निकलना मुश्किल हो गया है। जिन व्यापारियों से मनरेगा योजना के तहत पंचायत या सरपंच-सचिव ने खरीदी की थी उन व्यापारियों को अब तक भुगतान न होने पर नजरें चुराते फिर रहे हैं। व्यापारियों के फोन तक नहीं उठाकर पा रहे हैं। समस्या यह है कि, जवाब दे तो क्या दें...? क्योंकि सरकार की तरफ से होने वाले भुगतान को लेकर उनके पास सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही है। कुछ तय नहीं है कि, भुगतान कब तक और कैसे होगा...?

मंगलवार को झाबुआ में राष्ट्रीय सरपंच संघ के नेतृत्व में सरपंचों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय भारी प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट डॉ. जगदीश ठाकुर तथा जिला पंचायत के सीईओ जितेंद्र सिंह को जापन सौंपा। इस प्रदर्शन को और भुगतान ना होने को लेकर सरपंचों में भारी आक्रोश देखा गया। ज्ञापन के माध्यम से जिले भर के सरपंचों ने प्रशासन को 10 दिन का समय दिया है।

यदि तय समय में उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो उन्होंने कलेक्ट्रेट का घेराव करने और भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है। सरपंच संघ की मुख्य मांग है कि, ग्राम पंचायतों को उनके पंचायती राज व्यवस्था के अधिकार और पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता दोबारा सौंपी जाए। जिले की 367 ग्राम पंचायतों में पिछले लंबे समय से मनरेगा और अन्य विकास कार्यों की राशि अटकी हुई है। भुगतान न होने की वजह से गांवों में विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं और मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल पा रही है। जिलाध्यक्ष मुकेश मैड्रा के नेतृत्व में सरपंचों ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक विस्तृत मांग-पत्र प्रशासन को सौंपा। जिसमें 17-18 सूत्रीय मांग रखी गई है।

सरपंचों का कहना है कि, उनके कार्यकाल के 4 साल बीतने के बावजूद ग्राम पंचायतों को पर्याप्त फंड नहीं दिया जा रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर काम करना मुश्किल हो गया है। जबकि पड़ोसी जिले आलीराजपुर में नई योजना वीबी जी-रामजी के तहत हर पंचायत को बीस-बीस कुए मिल चुके हैं। झाबुआ जिले में भी प्रशासन मुस्तेदी दिखाए और पुराने भुगतानों का निराकरण कर नई जी राम जी योजना के तहत जिले में भी हर पंचायत को बीस-बीस कुए दिलाए जाए।

कुल मिलाकर झाबुआ जिला, तंत्र की कमजोर और भ्रष्ट कार्यप्रणाली के चलते लगातार पिछड़ता जा रहा है। जब प्रदेश के अन्य जिलों में नई वीबी जी-रामजी योजना के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं, तब झाबुआ जिले के सरपंच पुराने मनरेगा के अटकें करोड़ों भुगतान को लेकर मनरेगा के चक्रव्यूह में फंसे पड़े हैं और आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। नई वीबी जी राम जी योजना की तकनीकी दिक्कतें भी जिले के सरपंचों को खासा परेशान कर रही है।

मंंत्री की विधानसभा क्षेत्र में आंगनवाड़ियों का बे हाल, तीन साल से मध्यान्ह भोजन नहीं मिला

कच्चे किराए के भवन में चल रही आंगनवाड़ी, नई आंगनवाड़ी डेढ़ साल से अधूरी लोगो ने बना दिया शौचालय, ग्राम सभा में हुई पुष्टि

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

मध्यप्रदेश शासन की महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया के विधानसभा क्षेत्र में उन्हीं के विभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। जिसके बाद मंत्री और सरकार की कार्य प्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि, आखिर सरकार केवल सरकारी योजनाओं को विभाग के अधिकारियों के माध्यम से केवल कागजों पर ही चला रहे हैं, वास्तविकता से इनका कोई लेना-देना नहीं है। बहुत ही गंभीर मामला पेटलावद विकास खंड की ग्राम पंचायत बोझायत से सामने आया है। जहां 8 अक्टूबर को ग्राम पंचायत के ग्राम मोवड़ीपाड़ा में हुई ग्राम सभा में गांव के तड़वी फलिये स्थित आंगनवाड़ी में बच्चों को विगत तीन साल से मध्यान्ह भोजन नहीं मिलने की शिकायत ग्रामीणों ने की। मामले की पुष्टि आंगनवाड़ी में कार्यरत कार्यकर्ता ने भी की। जिसके बाद बैठक में उपस्थित ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव ने ग्राम में ठहराव प्रस्ताव बनाया जिसमें इसकी पुष्टि की गई कि, बच्चों को भोजन नहीं दिया जा रहा है। नियमानुसार आंगनवाड़ी में समूह अटैच किया हुआ है जो माध्यान्ह भोजन की व्यवस्था करता है। योजना के देख-रेख के लिए पूरा विभाग बना हुआ है। ग्राम पंचायत सहित आंगनवाड़ी में उपस्थित कर्मचारी द्वारा मध्यान्ह भोजन हेतु तय हुए समूह के लिए अपनी और से सहमति देते हैं। समय-समय पर इसकी जांच पड़ताल होती है। ऐसे में इतने लंबे अन्तराल तक मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन

नहीं होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन सभी की नाक के नीचे इतनी बड़ी लापरवाही चलती रही और कोई जवाबदार इसके बारे में जानकारी नहीं ले पाया...? ये एक बड़ा सवाल है।

मंत्री निर्मला भूरिया की विधानसभा में ही ये हाल

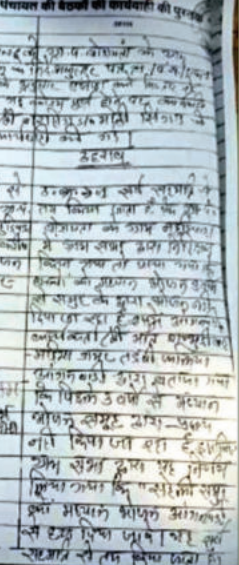
आंगनवाड़ियों और शासन की संचालित होने वाली योजनाओं की ये दुर्दशा तब है जब खुद मंत्री निर्मला भूरिया जिनके पास महिला बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी है। उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में अगर आलम ये है तो अन्य स्थानों पर क्या स्थिति होगी...? जिस स्थान पर आंगनवाड़ी किए के कमरे में संचालित हो रही है, उसकी स्थिति तक जरूर है, बच्चे आंगनवाड़ी से बहार बैठ कर पढ़ रहे हैं।

ग्रामीणों ने जब आंगनवाड़ी भवन पर जाकर वीडियो बनाया तो आंगनवाड़ी में मौजूद कार्यकर्ता ने कैमरे पर इसकी पुष्टि की कि, बच्चों को मध्यान्ह भोजन लंबे समय से नहीं मिल रहा है और पिछले साल केवल तीन दिन भोजन बच्चों को मिला था? शासन के मेन्यू में तो बच्चों के लिए कई पोषण आहार आंगनवाड़ियों के माध्यम से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दिया जा रहा है। ऐसे में विचारणीय है कि, बाकी योजनाओं का क्या हो रहा होगा। क्या ज्यादातर कार्य कागजी खानापूर्ति से निपटाए जा कर बड़े स्तर पर आंगनवाड़ियों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है? आंगनवाड़ियों के नाम पर आने वाली कोई सामग्री तक वहां ग्रामीणों को दिखाई नहीं दी।

नए भवन को लोगों ने बना दिया शौचालय, खंडहर में बदला भवन निर्माण

सरकारी राशि का किस तरह से दुरुपयोग और भ्रष्टाचार किया जा रहा है यहां मोवड़ीपाड़ा फलिया में देखने पर आसानी से मिल जाएगा। शासन करोड़ों रुपए खर्च कर नये भवन तैयार करवा रही है। लेकिन कहीं भ्रष्टाचार तो कहीं बजट की कमी के चलते आधे अधूरे भवन खंडहर में तब्दील हो गए और उक्त भवन आम ग्रामीणों के लिए शौचालय और सामान रखने के उपयोग में आ रहे हैं। उक्त फलिये में सरकार द्वारा आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत किया जिसका निर्माण विगत डेढ़ साल से अधिक समय से बंद पड़ा है। आधा अधूरा निर्माण भी अब खंडहर में तब्दील हो गया है।

ग्रामीण पप्पू सिंगाड ने जब ग्राम पंचायत सचिव से इसकी जानकारी ली तो मंत्री ने बजट नहीं होने का बोल के पल्ल झाड़ लिया। शनिवार को उक्त आंगनवाड़ी का वीडियो वायरल होने के बाद रविवार को आंगनवाड़ी सुपर वाइजर गांव में पहुंची लेकिन उस आंगनवाड़ी तक नहीं पहुंची। ग्रामीण पप्पू सिंगाड ने बताया कि, फोन लगाने के बाद भी मैडम यहां नहीं आई और हमको दूसरी जगह



- ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव में मध्यान्ह भोजन तीन वर्ष से नहीं मिलने की पुष्टि।



- किराए के भवन में आंगनवाड़ी, बाहर बैठने को मजबूर बच्चे।



- डेढ़ वर्ष से अधिक समय से अधूरी पड़ी आंगनवाड़ी।

बुलाया। जब हम वहां पहुंचे तो पता चला कि, मैडम ग्रामीणों से बिना मिले अधूरे आंगनवाड़ी भवन का वीडियो बना कर निकल गईं।

जांच के घेरे में पूरा सिस्टम, जनसुनवाई में पहुंचा मामला

मामले में पूरा सिस्टम जांच के घेरे में है, जनपद पंचायत से भवन निर्माण की अनुमति ग्राम पंचायत के माध्यम से मिली है लेकिन कार्य अधूरा है और लंबे समय से बंद। ऐसे में सचिव, सरपंच, उपयंत्री से लेकर जनपद सीईओ की कार्य प्रणाली

संदिहास्पद है। वही आंगनवाड़ी में मध्यान्ह भोजन का पूरा कार्य महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी की देख-रेख में स्वीकृत होता है। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर समय-समय पर आंगनवाड़ी से जुड़ी व्यवस्था देखती है। वही जिस समूह की इस आंगनवाड़ी के लिए मध्यान्ह भोजन देने का आदेश हुआ क्या उसे फूला भुगतान मध्यान्ह भोजन के नाम पर किया गया है ? क्योंकि भुगतान नहीं होता तो अधिकारियों के सज्ञान में इसकी जानकारी आ ही जाती की यहां व्यवस्था बिगड़ी हुई है? मंत्री निर्मला भूरिया का विधानसभा क्षेत्र होते हुए भी न विभाग को इसका कोई डर है न

ही व्यवस्थाओं में कोई बड़ा सुधार। ऐसे में विचारणीय सवाल ये है कि, इस गंभीर मामले की जांच होगी या जांच के नाम पर लीपा पोती ? या एक ओर भ्रष्टाचार कर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? ग्रामीणों ने इसकी शिकायत मंगलवार को जन सुनवाई कार्यक्रम में भी की है। संभवतः उक्त मामला सोशल मीडिया और मीडिया के साथ-साथ अब जन सुनवाई के माध्यम से भी अधिकारियों के सज्ञान में आ गया होगा। लेकिन कार्रवाई के नाम पर ऐसे गंभीर मामले में भी अब तक कोई हलचल या पहल प्रशासन की और से नहीं देखी गई।